श्री रोशन लाल : मैं लास्ट में क्लैरिफिकेशन करूंगा।

SHRI RANBIR SINGH: He does not want any clarification . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please don't interrupt. I know what I am doing here. I am asking him. If all the Members do like this, then where is the need to have a Chair and where is the need to have a Minister here? Mr. Roshan Lai, you please have your say. The Minister is there to refute if there is anything wrong.

श्री रोशन लाल : एक चीज मैं और कहना चाहता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What is the clarification?

SHRI ROSHAN LAL : Delay tactics

(Interruptions)

सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार को यह हिदायत की थी कि हर महीने 2000 परिवारों की आबादकारी की जाय लेकिन राजस्थान सरकार वहां पर डिले टैक्टिस लगाती रही और उन्होंने इन्कार कर दिया कि हम दो हजार नहीं ले सकते। उस हिसाब के अनुसार हर तीसरे दिन ढाई सौ फैमलीज को वहां जाना था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : How yo take your seat . . .

श्री रोशन लाल : अब हम पर डिले टैक्टिस का इल्जाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिमाचल गवर्नमेंट मदाखलत करती है। मैं यह वाजे कर देना चाहता हूं कि हम 250 फैमलीज हर तीसरे दिन उन के यहां भेजना चाहते थे उसके लिए उन्होंने इन्कार कर दिया। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो आज वहां पानी भर रहा है और 70 हजार आदमी जो वहां पानी के नजदीक बैठे हुए हैं क्या आप उनकी वार फुटिंग पर मदद करेंगे और मिलिटरी को हिदायत करेंगे कि उन की मदद करे इसलिये कि हर आदमी अपने डंगर, पशु और अपना सामान अपने साथ ले जाना चाहता है। वहां जाने से कोई इन्कार नहीं करता, लेकिन क्या आप उन को वहां ले जाने से इन्कार करते हैं। हम किसी नैशनल इंटरेस्ट में बीच में नहीं आना चाहते और हम को पानी देने से भी कोई इन्कार नहीं है। हम तो फकत उनका रिहैबिलिटेशन चाहते हैं। पंजाब को, राजस्थान को और हरियाणा को आज हिमाचल का पानी जाता है और जिस की वजह से वहां गंदम काफी हो सकता है। तो आप इन बातों का जवाब दें।

DR. K.L. RAO : Sir, I am glad on account of the sentiments he has expressed. That is a very happy sign. I should like to submit this . . .

SHRI JAGDISH PRASAD MA1HUR: He has alleged something against the Rajasthan Government . . .

DR. K. L. RAO : Sir, lam glad on ac-are not closed, the water will rise up to 1325 . . .

SHRI RANBIR SINGH : Water will remain on the dam for only 4-5 days?

DR. K. L. RAO : Even when the tunnel is not closed, the water will rise to 1325. About 14000 people will be affected. I will request the hon. Member- from Hima-chal Pradesh and his friends that they use their best efforts to get these people out of this 1325. Water may get there any time in the month of July.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, now we come to the Finance Bill. Mr. Shejwalkar.

SHRI RANBIR SINGH: There is one thing, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no question of anything now.

THE FINANCE BILL, 1973— *contd.*

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) : माननीय उप-सभापति महोदय, आज सदन के सामने 1973 का यह वित्त विधेयक विचार के लिये है। पच्चीस वर्ष स्वतन्त्रता के आने के बाद हो गये हैं और उसकी सिलवर जुबली मनाई जा रही है, यह रजत-जयन्ती वर्ष है और इस रजत-जयन्ती के वर्ष में दुर्भाग्य से चारों तरफ भूख, दंगे, बिजली का अभाव है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, पानी का अभाव है। यह सारी जो स्थिति है वह आज हम देख

रहे हैं। वैसे तो देखा जाय तो जब-जब भी फरवरी का महीना आता है और 28 फरवरी की तारीख आती है तो सारा देश एक तरह से घबड़ाहट में आ जाता है, उसको एक घबड़ाहट होती है कि न मालूम कौन से नये-नये कर अब लगने वाले हैं और अब न मालूम क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं और उसके बाद सारा उसका जो परिणाम है, वह सारे भारतवर्ष को भुगतना पड़ता है।

'गरीबी हटाओ' का नारा लगाये हुये दो वर्ष हो गये। कभी कह दिया जाता है कि गरीबी तो मेरी जिन्दगी में भी नहीं हट सकती और कभी फिर कहा जाता है कि हम तो गरीबी हटाने के लिये बन्धे हुये हैं। कभी हमारे वित्त मंत्री महोदय उपदेश देते हैं कि होल्ड दि प्राइस लाइन, प्राइस लाइन को पकड़ कर रखो। मैं जब विद्यार्थी था तो ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता था—लाइन हैज लैंथ बट नो ब्रेथ—इसलिये यही कारण है कि उनको इस लाइन को पकड़ना ही नहीं आता, क्योंकि ब्रेथ है ही नहीं तो कहां से पकड़े। तो यह स्थिति है कि हर बार कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। बजट जब लाया गया तो एक फैलेसी सामने थी, उसके पहले पिछले सत्र में पे कमिशन की रिपोर्ट के बारे में इसी सदन में प्रश्न उपस्थित हुआ और यह मांग की गई—मैंने भी प्रश्न पूछा था कि क्या आप सहानुभूतिपूर्वक यह विचार करेंगे कि कुछ अंतरिम सहायता दी जाय तो उन्होंने कहा कि सहानुभूति तो है लेकिन अंतरिम सहायता हम नहीं देंगे। अब उसका कारण स्पष्ट था कि बजट को रखना था, उसमें 85 करोड़ रु० का घाटा प्रस्तुत किया गया और जब रिपोर्ट आयेगी तो उनको पता था कि उससे भी सैकड़ों करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है और उसके अनुसार फिर दुबारा इनफ्लेशन के लिये, महंगाई के लिये, बड़ा भारी प्रश्न उपस्थित होने वाला है।

इधर इन सारी समस्याओं का कारण हमारी प्रधान मंत्री जो विरोधी दल है, उनके ऊपर थोपने में भी कभी चूकती नहीं हैं. आये दिन ये भाषण होते हैं कि इस सारे के लिये उत्तरदायी जो है वह विरोधी दल है, हम जो कुछ योजनायें सामने रखते हैं उन योजनाओं में ये किसी प्रकार से हमें सहयोग नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी जनतन्त्र के अन्दर उत्तरदायित्व पहला, प्रमुख रूप से किसका है ? जो शासक दल हो, जो दल इतने बड़े बहुमत में हो सारा उत्तरदायित्व उसी का है। दूसरा अगर कोई सहयोग चाहता है तो आखिर जो विरोधी दल है वे इनके बनाये हुए नहीं हैं। उनका भी अपना-अपना महत्व है और अपनी-अपनी मान-मर्यादा है। आप कोई नीति निर्धारित करते हैं, बनाते हैं अपने आप और फिर आप दूसरों से कहते हैं कि उसका पालन करो और वे लोग इस बारे में अपनी राय भी जाहिर न करें तो आप उनसे कहते हैं कि ये तो हर चीज में रुकावट डालना चाहते हैं। अगर राष्ट्र के बारे में कोई समस्या है और उस समस्या को वास्तविक रूप से आज का शासन हल करना चाहता है, तो उसको विरोधी दल को बुलाना चाहिये, उनसे अलग से बात करनी चाहिये कि उनको इस बारे में क्या राय है ? हो सकता है कि इस तरह की बातचीत के बाद भी कोई नतीजे पर न पहुंचा जाय, विरोधियों से राय न मिले, एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद भी कोई नतीजा न निकले, तो उसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि हम आप का इस बारे में सहयोग चाहते हैं। लेकिन एक दिन कोई महानुभाव किसी अधिवेशन में किसी चीज को अचानक रख देते हैं और उस चीज के बारे में जब कि उनके दल में ही दो राय हैं, उस चीज के बारे में कहते हैं कि विरोधी लोग इस चीज को नहीं करने देना चाहते हैं और हमारे रास्ते में अड़ंगा लगाना चाहते है। पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न आया तो उस समय भी यही कहा गया था कि हम लोग तो प्रगति करना चाहते है, लेकिन विरोधी लोग हमारे मार्ग में बाधक हैं, हम प्रिवी पर्स समाप्त करना चाहते हैं, मगर ये नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से ये लोग हमारे रास्ते में रुकावट डालना चाहते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपने दो काम कर लिये, क्या उनमें आपको रुकावट आई ? एक मामले में कुछ रुकावट आई कि मामला

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

कोर्ट में गया, लेकिन उसके बाद तो आपका काम हो गया । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका परिणाम क्या निकला? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमेशा से यह कहते आ रहे हैं कि इन चीजों से गरीबों को लाभ होगा बैंक के राष्ट्रीयकरण करने से । आज यह स्थिति हो गई है प्राइवेट बैंकों से जहां पहले जनता की सेवा होती थी; क्योंकि स्टेट बैंक को तो सरकारी काम-काज से ही फुरसत नहीं मिलती है, लेकिन आज राष्ट्रीयकरण करने के बाद से उन बैंकों में भ्रष्टाचार फैल गया है । पहले मुझे उनके कार्यप्रणाली के के बारे में बड़ा गर्व था, लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि उन बैंकों के अन्दर भी भ्रष्टाचार घुस गया है । अगर किसी गरीब काश्तकार को 500 रुपये का कर्जा लेना होता है तो उसके हाथ में केवल 200 रुपया ही मिलता है । आज जो गरीब लोग हैं उनको इन बैंकों से किसी तरह की भी मदद नहीं मिल रही है । मैं आपके सामने मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर इंजीनियरों को 20 लाख रुपया कर्जा देने की बात थी और यह कर्जा वहां पर तीन लड़कों को मिला । इनमें से एक लड़का तो चीफ सेक्रेट्री का था, दूसरा एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का था और तीसरा एक बड़े अधिकारी का लड़का था। इस तरह से जो 20 लाख रुपया बेकार इंजीनियरों के लिए था, वह इस तरह से तीन लड़कों को दे दिया गया ।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): यह कहां की बात है ।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : यह मध्य प्रदेश में, भोपाल की बात है । इस तरह का मारुति लिमिटेड का एक बहुत बड़ा किस्सा हो गया है । यह कम्पनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई और न इसको अभी लाइसेंस ही मिला, लेकिन इसको फाइनेन्स कारपोरेशन से लाखों रुपया कर्ज के रूप में मिल गया है । इस तरह की बात पहिले नहीं होती थी । कुछ मात्रा में होती होगी, लेकिन आज तो इस तरह की बात ह आम बात हो गई है ।

अब सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ म ले लिया है । आप अगर यह समझते हैं कि हम इन व्यापारियों के हमदर्द हैं तो मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें व्यापारियों से कोई बड़ी हमदर्दी है, इस तरह की जो बात आपके मन में है उसको आप मन से निकाल दीजिये । लेकिन जो कोई समाज विरोधी तत्व है, उनके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है । मैं यह शब्द "जो कोई" के ऊपर विशेष बल दे रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ सरकारी अधिकारीगण भी इस कार्य में लगे हुए हैं तथा कुछ अन्य लोग भी है जो इस तरह के कार्यों में मिले हुए होते हैं । इस तरह के लोगों के लिए आपने कोई योजना और कोई उपाय नहीं किया । इसी बात पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि हम देखते हैं हैं कि मध्य प्रदेश से जो इंस्पेक्टर गेहूं खरीदने हरियाणा गये थे, उन्होंने एक रुपया बोरी वसूल किया । भाव कुछ भी हो, 74,76 या 82, यह उनके ऊपर निर्भर होता है । क्या आप इन्हीं के आधार पर योजनाओं को सफल बनाने की बात सोचते हैं ?

बड़ी खुशी की बात है कि आपने इन्कम टैक्स एक्ट में एक प्रावधान कर दिया कि कोई कम दर पर अपनी सम्पत्ति को बचेगा तो सरकार को उसको लेने का अधिकार हो सकता है । मैं एक दूसरी बात रखना चाहूंगा—मैंने पिछले वर्ष भी वित्त मंत्री महोदय से सवाल किया था और आज भी जानना चाहूंगा—कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर कीमत ज्यादा लगा कर एसेसमेंट करने की कोशिश करे तो ऐसे भी यह कह सके कि सरकार यह कीमत निर्धारित करती है तो सरकार इस कीमत में ले ले, आप्शन उसको भी हो । यह सब मिली भगत है । आपका टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वह बहुत कम्प्लीकेटेड है, उसमें बहुत लूपहोल्स हैं । इसके कारण दोनों मिल कर जनता के धन को लूटते हैं । आज आपने चाहे राजा खत्म कर दिए होंगे, लेकिन आज दूसरे राजा बन रहे हैं । आज एक साधारण मोटर वैहिकिल्स का टैक्स इंस्पेक्टर कार रख सकता है, जिसकी 250—300 तनख्वाह होती है । पुलिस का इंस्पेक्टर, जिसकी 250—300 तनख्वाह होती है, 200 रुपये महीना मकान का किराया दे सकता है, 100 रुपए की ट्यूशन रख सकता है और 500 रुपये के उसके अपने निजी नियमित खर्चे हैं, यह सब बना सकते हैं । आज

चम्बल का पुल टूट गया, फलां जगह का पुल टूट गया, इनक्वायरी बैठ गई। पी० डब्ल्यू० डी० में क्या है ? हर विभाग में यही हाल है। फारेन एक्सचेंज बिल पर चर्चा का मौका मिला था। लाखों रुपये की स्मगलिंग होती है। अगर हम और आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए बराबर कानून का पालन होगा, अगर आप एक शर्ट का कपड़ा भी ले आये तो पैनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं देखता हूं कि हजारों घड़ियां, हजारों ट्रांजिस्टर, हजारों टेलीविजन, मोटरें भी, रेफ्रीजैरेटर सब यहां आ जाते हैं। क्या ये सब यों ही पास हो जाते हैं ? जो स्मगलिंग करते हैं और जो उनके साथ मिले होते हैं, उन दोनों की साठ-गांठ होती है। इसको प्रश्रय देने वाले हैं राजनीतिज्ञ, जो अपने दल के हित के लिए या अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए ऐसे तत्वों को प्रश्रय देते हैं। आपने इस समस्या के मूल्य को देखने का प्रयास नहीं किया। मैं चेलेंज देकर पूछना चाहता हूं —आप जनसंघ को बराबर दोष देते हैं —आप बताइए कि कितने बड़े व्यापारी हैं अनाज के जो हमारे साथ लगे हैं। एक-दो प्रतिशत होंगे। आप देखेंगे सारे खादी—वेशधारी शासन के पीछे, अधिकारियों के पीछे घूमने वाले लोग नजर आएंगे। हमको उनके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। हमको हमदर्दी किसानों से है, जनता से है। इस सबका परिणाम यह होता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी किसान को सही कीमत मिलने नहीं देते। हमें व्यापारी से कोई हमदर्दी नहीं है। आप उनको रोकेंगे जो एक-दो रुपया मुनाफा कमाते हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज 20 और 24 रुपए क्विन्टल पड़ते हैं, फूड कारपोरेशन देता है। फूड कारपोरेशन की हालत आपको पता है। हजारों टन गल्ला सड़ गया, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। उसके चेयरमैन, एफ० सी० आई० के चेयरमैन के खिलाफ क्या-क्या हुआ, आप सब जानते हैं।

आपका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर ही खराब नहीं है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी घाटा होता है। उसका भी कारण यही है। अब कोई आदर्श उपस्थित करने के लिए तैयार नहीं है। केवल कागजों में या भाषण देने से आदर्श उपस्थित नहीं होगा, व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं व्यक्ति को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर प्रधान मंत्री जी यह तर्क दें कि मैं अपने लड़के के लिए मोटर का कारखाना क्यों नहीं खोल सकती, उसने क्या गलती की है तो वह तर्क हर एक के लिए उपलब्ध होगा।

आज भारत के लिए त्याग की आवश्यकता है। अगर वह इस चीज को सामने रखते। इस प्रकार का आदर्श उपस्थित करते तो शायद दूसरे लोग भी उसकी मांग न करते तो आज देश के सामने दूसरा ही चित्र होता। मैं अपने बारे में भी कहता हूं कि अगर आज लोग आदर्श उपस्थित करें तो देश का उदाहरण ही दूसरा होता। लेकिन हम लोग बातें करते हैं पर उसके मूल को हम देखना नहीं चाहते। ऊपर-ऊपर मरहम पट्टी वाले हल निकालते जाते हैं, इसलिए हम दिन प्रति दिन नीचे चले जा रहे हैं।

ग्रोथ रेट हमारा कम हो गया। 900 करोड़ रुपये के लगभग हमारा उत्पादन इस वर्ष कम हो गया। बिजली की बहुत बड़ी कमी है। पावर शार्टेज की वजह से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। क्यों नहीं हम उसके बारे में एक ऐसी योजना बनाते कि जिसमें सारे समाज का एक-एक व्यक्ति सम्मिलित होकर उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर तैयार होता ? सारी चीज नारेबाजी से तैयार की जाती है। मुझे याद है कि सन् 1957 में अमरीकन कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम फर्टिलाइजर कंपनी खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय यह बात कही गयी कि 51 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के होंगे। लेकिन उस कंपनी ने सोचा कि इसमें रोज-रोज का इंटरफियरेंस होगा, हस्तक्षेप होगा और वह तैयार नहीं हुई। आज दुर्भाग्य यह है कि सर्व-साधारण और अधिकारियों के बारे में यह विश्वास नहीं है कि कोई ईमानदारी से या नेकनियती से काम करेगा। अगर हमारे पंडित जी इस बात पर न अड़े होते तो शायद उस समय फर्टिलाइजर्स आ गया होता और जो सूखे की स्थिति आज है वह न होती और हमारी योजना सफल होती।

कहा जाता है कि इन दिनों में हमने प्रगति की है और हमको फारेन टेकनीक की आवश्यकता

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

नहीं है । लेकिन मैं देखता हूं कि व्यावहारिक रूप में छोटी से छोटी मशीन क्यों न हो, हम नहीं बना सकते । आज युग कितना आगे चला रहा है, दुनिया की दौड़ में हम कितने पीछे है और फिर भी हम यह नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे यहां आये । यह मैं मानता हूं कि बैलेंस हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फारेन एक्सचेंज व्यर्थ न जाये, लेकिन इतनी सख्ती रखने से नतीजा यह होता है कि आपका उत्पादन कम हो रहा है । अगर आप ऐसी योजना बनायें कि उत्पादन ज्यादा हो और जितना फारेन एक्सचेंज बाहर भेजेंगे उससे ज्यादा कमाकर देंगे, इन टर्म्स पर कोलाबोरेशन करें तो बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है, इससे क्वालिटी देश में सुधर सकती है और देश में बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है । बहुत से देश हैं जिन्होंने यह बात तय की कि हम दूसरों को आने देंगे । हमारे देश का एक-एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि उसको देखने की जरूरत है, वह उसको नकल कर सकता है । रशियन्स में, हर बात में वह बुद्धिमान है उसको देखने का मौका तो मिले, काम करने का अवसर तो मिले । इसके बारे में एक ऐसी पालिसी आपकी है जिसके कारण आज हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं ।

अनएम्प्लायड लोगों का प्रतिशत पढ़े-लिखे अनएम्प्लायड लोगों का प्रतिशत 43 परसेंट बढ़ गया है । अब आप सोचिये कि 43 परसेंट बढ़ गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे गलत न समझें, मैं मोनोपोलिटों के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि एम्प्लायमेंट का अगर आप हिसाब लगायेंगे तो जब से आपने पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हाथ में ली है एम्प्लायमेंट पोटेंशल कम हो गया है । उसका कारण यह है कि उसमें आप लाभ नहीं कमा रहे है, विकास नहीं करते । प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स स्टाफ और दूसरों को ज्यादा पैसा देते हैं और हर साल नया कारखाना लगाते थे । उससे इम्प्लायमेंट पोटेंशल बढ़ता था । लेकिन आपकी पालिसी के कारण अनएम्प्लायमेंट का परसेंटेज बढ़ गया । इतने ज्यादा आज अनएम्प्लायड हो गये इंजीनियर कि वे आज बैंकों में नौकरी करते हैं ऐज ए क्लर्क । ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। तो यह स्थिति आज देश के अन्दर है और इस तरह की निराशा की स्थिति बनी हुई है । इसका कारण यह है कि इस अनएम्प्लायमेंट के बारे में दुर्भाग्य से आज इस सरकार का कोई दृष्टिकोण है नहीं जिसके कारण से आगे कोई हल नजर नहीं आता ।

इसी प्रकार से आपने बिजली के उत्पादन का काम किया । मुझे याद है कि पिछली बार जब बिहार में सूखा पड़ा था तो उस वक्त वहां संविद सरकार थी । उनमें चाहे जो भी दोष हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उस समय बिहार की सरकार ने जितना काम किया वह अनुकरणीय उदाहरण है । उन्होंने जगह-जगह पम्प लगाये, जगह-जगह उन्होंने पानी के लिए छोटा-छोटा प्रबंध किया ।

जिन स्थानों पर हम पानी के लिए आसमान की तरफ देखते हैं महाराष्ट्र में, मैसूर के कुछ क्षेत्रों में, वहां दो तीन रुपये मजदूरी से काम तो आपने करवाया, लेकिन उससे काम चलनेवाला है नहीं । वहां पर आप छोटे सिंचाई के साधन बनाते तो उसके कारण आप उसी के आधार पर आगे के लिए कम से कम इस समस्या को हल करने में सहायता दे सकते थे, लेकिन उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया ।

गरीबी का नारा दिया जाता है, लेकिन आज 75 प्रतिशत ऐसे गांव है जिनके अन्दर न बिजली पहुंची है और न पीने के पानी का प्रबंध है । आपके आवास मंत्रालय ने एक योजना बना दी कि इतने गांव हम प्रत्येक वर्ष लेंगे, लेकिन फिर भी छ. साल में सब पूरे नहीं किये जा सकते । आप प्रमुखता किस चीज को देने वाले हैं । पीने के पानी को आप देंगे नहीं । आप पम्पस वगैरह को प्रमुखता देंगे नहीं, आप उनके निवास लिये कोई योजना बनायेंगे नहीं, आप तो 26-26 मंजिल वाले भवन बनायेंगे और उनके लिए आप योजना बनायेंगे । आप ऐसी कोई योजना आरंभ नहीं कर सकते, जिसमें जनता का कोआपरेशन मिले

आप कालोनीज स्वयं बनाते हैं । मैं पूछना चहता हूं कि आप डोनेशन दे कर क्यों नहीं स्वयं उनसे उसको कराते हैं । आप उनको सबसीडी दीजिये । इससे मकानों की संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी और सरकार का इंवेस्टमेंट भी कम होगा । यह मानना पड़ेगा कि अब रूस में भी इस बात पर लोग वापस आने लगे हैं कि व्यक्तिगत जब तक किसी में भावना नहीं होती इंसेंटिव नहीं होता, तब तक काम में उसकी रुचि नहीं होती है । सरकार के मकान में लोग उसकी मरम्मत करने को तैयार नहीं होते हैं । अगर उसका किराया सौ रुपये होगा तो लोग चाहेंगे कि 50 रुपया ही देना पड़े । इसलिए अगर आप उसके ह्यूमन करेक्टर को कंसीडर कर के कोई आवास की योजना बनायें तो यह हो सकता है कि एक बड़ी भारी क्रांति आ जाय । अगर लोग स्वयं अपना मकान बनायेंगे तो उससे सरकार के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा । आप ह्यूमेन एप्रोच को एक तरफ रख देना चाहते हैं और केवल एक कागजी योजना बना कर चाहते हैं कि वह कार्यान्वित हो जाय और यही कारण है कि उसमें आपको असफलता मिल रही है । समाजवाद का हम नारा लगाते हैं, लेकिन समाजवाद वास्तव में क्या है इसके बारे में भिन्न-भिन्न रायें हैं। एक ही दल के अलग-अलग लोग अलग-अलग उस की व्याख्या करते हैं। अगर उसका अर्थ यह है कि हम विषमता को दूर करें तो हम उसमें साथ हैं। हम खुद विषमता नहीं चाहते हैं । हम नहीं चाहते हैं कि किसी को दो सौ रुपये तनख्वाह मिले और किसी को 5,000 रुपया मिले । हम ने कहा है कि एक और दस के बीच में उसका प्रमाण होना चाहिए, आय का और उसको आप करिये ।

आपने और तमाम दूसरे कानून बनाये लेकिन उसमें इस की कोई रोक नहीं की कि डिस्पैरिटीज को कैसे खत्म किया जाय । इसके लिए आप ने कोई योजना नहीं बनायी । अगर किसी को दस करोड़ की आमदनी हो जाय और वह बड़ी-बड़ी कोठियों में रहे तो उस पर आप किसी किस्म की रोक नहीं लगाना चाहते, आप उस पर कोई रोक लगा नहीं सकते । आज हम लोग स्वयं कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर रहे हैं । हम लोग चाहते हैं कि हम तो ढाई लाख की कार में घूमते फिरें और अपेक्षा करते हैं एक व्यापारी से कि वह किसी विदेशी कार का इस्तेमाल न करे । मैं समझता हूं कि इस बात का कोई वजन नहीं होगा । मैं यह बात समझ सकता हूं कि जो हमारे केन्द्र के मंत्री हैं, उन के जीवन का बहुत अधिक महत्व है । अगर कोई ऐसी नौबत आ जाय और आप को हिल्स आदि में दौरा करना हो तो आप उसके लिए कोई विदेशी या और अच्छी कार ले जायं, लेकिन अगर आप को दिल्ली में ही घूमना है तो फियेट या एम्बेसेडर में आप क्यों नहीं घूम सकते ? लेकिन आज ऐसी भावना हमारे मंत्रियों में नहीं है । आज ही मुझे पता लगा कि हमारे एक नये मंत्री हैं, जिन्होंने एक नयी विदेशी कार लेने से इन्कार कर दिया और अपने पुराने फ्लैट में ही रहना पसंद किया है । यह एक अच्छा उदाहरण है । अगर सभी लोग ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें तो एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है । कोई एक नया कानून बनाने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सकता हम गलती करें और दोष विरोधियों पर मढ़ दें यह ठीक नहीं है । आज कहा जाता है कि विरोधी हमारे दल को सैलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चुनाव किस तरह से जीते हैं । यह चुनाव विरोधियों को सेलाइन कर के ही तो जीता गया है । मेरा तो आरोप है कि विरोधियों को सेलाइन करके तो वह लोग यहां आये हैं । हम कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं । हमारे संगठन में अनवर देहलवी हैं, हमारे यहां अब्दुल रहमान हैं, कानपुर में एक मुसलमान हमारे मेम्बर हैं, लेकिन उस सब बात को वह नहीं मानेंगे । इसके बाद भी वे नहीं मानेंगे कि हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं । समझते हुए भी वे कहते रहेंगे कि हम लोग सांप्रदायिक हैं । व्यापारियों से वे चन्दा खुद ही इकट्ठा करते रहेंगे और आरोप हम पर लगायेंगे कि हम उन से पैसा ले रहे हैं और हम व्यापारियों से मिले हुए हैं । आपके यहां साठ-साठ लाख रुपये की रकम का कोई पता नहीं चलता, उस के बारे में आज तक कोई सही स्टेटमेंट नहीं दिया जा

[श्री ना० कु० शेजवलकर]

सका और आरोप हम पर लगाया जा रहा है। समाजवाद का नारा लगाते हैं और एक प्राइवेट कम्पनी खुद ही घर में चला दी जाय तो उस में दोष किसका है? इसमें हमारी पार्टी का कोई दोष है या आप का? मेलाइन आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? तो आप देखें कि वास्तविक स्थिति आज क्या है। टैक्सेशन ला आप ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, उसमें इतने डिडक्शन्स होते हैं और इतने झगड़े करने पड़ते हैं कि उसके कारण वह सिम्पुल नहीं रहा है जब कि कानून साधारण व्यक्ति की समझ में भी आना चाहिए। मैं भी 27 साल की स्टैंडिंग का वकील हूं, लेकिन मुझे भी तीन-तीन बार कुछ बातों को देखना पड़ता है और इनकम टैक्स के रेगुलर प्रेक्टीशनर्स से पूछना पड़ता है। मैं तो कोई पापुलर मंत्री नहीं हूं कि दस साल तक रिटर्न दाखिल न करने पर भी कह दूं कि रिटर्न दाखिल करना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो लॉ को सिम्प्लीफाई करने का प्रयत्न होना चाहिए

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। मैं कोई अनुभवी वकील तो नहीं हूं 27 वर्ष की प्रैक्टिस की, लेकिन आपने कहा कि हम विरोधियों को मेलाइन कर के ही इस चुनाव में जीत कर आ सके हैं। तो क्या आप ऐसा कह कर जनता की समझदारी को चुनौती नहीं दे रहे हैं? जनता ने जिन को चुन कर भेजा है, उस जनता को आप चुनौती नहीं दे रहे हैं, उसकी समझदारी को।

श्री ना० कु० शेजवलकर : मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। जनता के ऊपर हमारी अपार श्रद्धा है, लेकिन जनता तो ऐसे भोलेशंकर है। उस को समझ का सवाल ही नहीं है। भोलेशंकर जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार जनता को जिसने डमरु बजा कर रिझा लिया वह उस की बात मान जाती है. .

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : आप तो तांडव भी करते हैं तो भी कुछ नहीं होता।

श्री ना० कु० शेजवलकर : तो मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ मैंने यहां संक्षेप में निवेदन किया है, उस पर आप गौर करें और शान्तिपूर्वक विचार करें और मैं समझता हूं कि आप अपने मूलभूत विचारों में कुछ परिवर्तन करें तो शायद हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप के किसी नेक कदम में हम आप के साथ हैं और हम उसके लिए हर प्रकार से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, आप कोई सेक्रीफाइस बाद में करें, हम पहले करेंगे। आप निर्धारित कर दीजिए कि सब एम०पीज० को हम दो सौ रुपये महीना तनख्वाह देंगे, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे आप आधी तनख्वाह ही दीजिए। लेकिन आप आदर्श उपस्थित करें, हम आपके साथ आने को तैयार हैं।

श्रीमती सीता देवी (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, इस वर्ष इस बजट को संतुलित बनाना और आर्थिक व्यवस्था के मुताबिक बनाना काफी कठिन काम था; क्योंकि सन् 1971 ई० में देश ऐसी परिस्थितियों में से गुजरा, बंगला देश का प्राबलम था और कई जगह पर अकाल पड़ा। मैं समझती हूं कि इन हालात में जिस किस्म का बजट हमारे वित्त मंत्री साहब ने बनाया और कोशिश की कि गरीबों के ऊपर कम से कम भार पड़े इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि कितने नेक कदम उन्होंने उठाने की कोशिश की और दिल से कोशिश की, लेकिन हमें एक खदशा यह है कि जो नेक कदम उन्होंने उठाया और उठाने की कोशिश की उसके बावजूद ऐसा न हो और जैसा कि हम देखते हैं कि जिस किस्म से हमारे काम चलते हैं, उससे वह लाभ नहीं हो पाता जो कि होना चाहिये। जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका पहला अभिप्राय यही था कि जो गरीब लोग हैं, किसान मजदूर हैं, गरीब जनता है, उनको किसी प्रकार से लाभ हो, उनको कोई लोन मिले, वह कोई छोटा-मोटा व्यापार कर सकें, कोई रिक्शा वाला रिक्शा बना ले, कोई स्कूटर वाला स्कूटर बना ले, कोई टैक्सी बना ले और वह अपना व्यापार करे। मेरा अपना अनुभव है क्योंकि मैं गरीब लोगों के अन्दर, मजदूरों में,

काम करती हूं, कि उसका वह लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसा लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है कि उन प्रोसीजरों में से जो गरीब आदमी है उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है—यह सिक्योरिटी लाओ, वह सिक्योरिटी लाओ और फिर बीच में जैसा कि हमारा कैरेक्टर है कुछ रुपया भी लेते हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि उन प्रोसीजरों को जैसे भी हो कुछ सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करें। 14 करोड़ रुपये के डाइरेक्ट टैक्सेज लगाये गये हैं और बाकी इनडाइरेक्ट टैक्सेज लगाये गये हैं। ठीक है, टैक्सेज लगाना बड़ा जरूरी है, जिस देश ने आगे बढ़ना है, आगे प्रगति करनी है, फाइव ईयर प्लान्स को पूरा करना है, तो टैक्सेज तो लगाना ही है, बिना टैक्सेज के तो काम नहीं चलता लेकिन टैक्सेज वह लगाना चाहिये जिनका कि जो गरीब है जो मध्यम वर्ग है उसके ऊपर बहुत कम असर पड़े। मैं बहुत वर्णन नहीं करना चाहती, लेकिन पैट्रोल के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने 8 पैसा लगाया है, देखने में तो 8 पैसा बड़ा कम लगता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा है? आप देखिये कि स्कूटर है, टैक्सी है, कारें हैं, उनमें किराया बढ़ गया। क्यों किराया बढ़ गया? वह सीधे कहते हैं कि आपकी सरकार ने पैट्रोल महंगा कर दिया। इसका जो मध्यम वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार से जो स्टेनलैस स्टील है और जो छोटी-छोटी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पारिवारिक रूप से एक मध्यम वर्ग के परिवार को है, उसका बहुत ज्यादा बोझा उनके ऊपर पड़ा है और उनको बजट संतुलित करना मुश्किल हो गया है।

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि बड़ा अच्छा होता कि आप शराब के ऊपर दुगुना टैक्स लगा देते, अगर वह यह करते तो मैं बड़ा मुबारकबाद देती मिनिस्टर साहब को। यह शराब जिसकी कि पंजाब के अन्दर एक एक फर्लांग पर दुकानें खुली हुई हैं जिसके पीने से हमारा भारत इतना गिर रहा है, उस शराब के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स लगा देते तो इससे रेवेन्यू भी हो जाती और शायद गरीब आदमी को उसके कुछ कम पीने से बचत भी हो जाती। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया और क्यों यह उचित नहीं समझा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : आपकी गवर्नमेंट को हानि होती इसमें।

श्रीमती सीता देवी : चलिये, वह तो ऐसा ही है, गवर्नमेंट तो चलानी ही होती है। दूसरी एक और चीज है जिसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं, वह यह है कि हम जिस समाजवाद को लाना चाहते हैं और हम जो चाहते हैं कि गरीब और किसान और मजदूर और अमीर में अन्तर खत्म हो जाय, कम हो जाये एक और

4 P. M. दस का हो जाए। वह कैसे हो सकता है? जब तक हम उसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे और मैं यह समझती हूं, जब तक हमारे देश के अंदर से ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा, तब तक देश में समाजवाद कभी नहीं आएगा चाहे हम उसके लिए कितनी भी कोशिश करें। उसके लिए बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रांग मेजर्स लेने पड़ेंगे, इस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। मेरे दिल में एक सुझाव है, जैसा लंका के अंदर किया गया था कि एक ही रात में आर्डर किया गया था कि जो 100 रु० के नोट हैं व बाहर निकल आएं, वे आगे नहीं चलेंगे। जो लोग इन नोटों को दबा कर रखे हैं आखिर किसी शक्ल में—100 रु० के 500 रु० के या 1,000 रु० के—रखे होंगे और अगर हमारी गवर्नमेंट मुनासिब समझे इस किस्म का डिक्लेयर कर दे कि वे आगे नहीं चलेंगे। लेकिन यह न हो जैसा कि अब की हुआ कि जमीनों की सीलिंग होनी है कहा, तो लोगों ने जमीन अपनी-अपनी सम्भाल ली, इसके नाम कर लिया उसके नाम कर लिया ताकि कोई जमीन बचे नहीं। मुझे तो पंजाब का अनुभव है, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो उसके मुजारे थे—इसके नाम 400 एकड़, उसके नाम 400 एकड़ रख कर जमीन की सीमा को खत्म कर दिया और उनसे प्रो-नोट लिखवा कर रख दिया। अब उस गरीब के नाम न 20,000 रु० होगा, न वह

[श्रीमती सीता देवी]

जमीन का मालिक बनेगा। जमीन का मालिक वह जमींदार खुद का खुद ही रहा। यह जो मैं आपको बता रही हूं यह बिलकुल एक फैक्ट है, जो कुछ वहां हुआ है और सूबों में भी हुआ है। मैंने पंजाब का वाक़या आपके सामने बताया। तो अगर बात पहले निकल जाए गवर्नमेंट से तो जो पूंजीपति हैं, जो एपार्चेनिस्ट लोग हैं वे सावधान हो जाते हैं। मेरा तो विश्वास है कि यह बड़ी भारी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी इस सरमायादारी के खिलाफ, अगर हमें सचमुच में समाजवाद लाना है। जैसा आपने देखा जजेज के केस में तूफान मचा हुआ है, नीचे की दुनिया ऊपर आ गई है। क्यों आ गई है? आफटर आल, अगर हमने उन नीतियों को इम्पलीमेंट करना है जो समाजवाद की नीतियां है, तो उसके लिए हमें सुधार करने पड़ेंगे, उसके लिए अपना रेडिकल स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप उठाया गया है, जिसके लिए तूफान मचा है। इसी तरह से मैं कहना चाहती हूं ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक बड़ा भारी रेडिकल स्टेप उठाना पड़ेगा। मेरा एक सजेशन था--मिनिस्टर साहब इसके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं--एक और चीज़ है जो कि हमें करप्ट करती है और वह यह कि चाहे एम० एल० एज० हों, चाहे एम० पीज़० हों, आए दिन वे पार्टी बदलते हैं--सवेरे एक पार्टी में है, दोपहर को दूसरी पार्टी में हैं और शाम को तीसरी पार्टी में है। किसी ने 20 हजार रु० दे दिया, दूसरे ने 30 हजार रु० दे दिया, तीसरे ने 40 हजार रु० दे दिया। यह चीज जहां करप्ट करती है वहां उनके कैरेक्टर को भी गिराती है और ब्लैक मनी बढ़ता है, साथ ही ब्लैक मनी वालों की हिम्मत बढ़ती है। तो कोई ईमानदार आदमी 20,000 रु० किसी को यूं ही नहीं दे सकता, वही देगा जिसके पास ब्लैक का रुपया है। वह सोचता है कि मेरी पार्टी वाले आदमी की हुकूमत होगी तो वह हमें और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अगर 10 लाख रु० एक ब्लैक मार्केटियर उसके लिए इकट्ठा करता है तो उसको 10 करोड़ रु० कमाने की आशा रहती है। वह इसमें प्राफिट की आशा रखता है। तो मैं सोचती हूं, जब तक यह ब्लैक मनी हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाजवाद नहीं आ सकता।

एक और सजेशन है। महंगाई बेहद बढ़ रही है इसलिए जो आर्गेनाइज्ड लेबर, है, आर्गेनाइज्ड यूनियन है, वह आए दिन आंदोलन करती है, आंदोलन करके उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ठीक भी है, बढ़नी भी चाहिए, महंगाई जो है, पर उनकी तनख्वाहें बढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि महंगाई दुगुनी बढ़ जाती है। इसलिए मेरा सजेशन है मिनिस्टर साहब से कि क़ीमतें जो हैं, खास तौर से जो खाने पीने की चीजें हैं, जिन्हें गरीब और मिडल क्लास ने खाना है, जैसे चावल है, तेल है, वनस्पति घी है, और रोजाना इस्तेमाल के लिए साबुन है, तेल है, मोटा कपड़ा है, इनकी क़ीमतें फ्रीज कर दी जाएं। जब तक आप क़ीमतें फ्रीज नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही तनख्वाह बढ़ाते चले जाएं, सरकारी नौकर भी संतुष्ट नहीं होंगे, जो मजदूर वर्ग है वह भी संतुष्ट नहीं होगा।

मैं तो इस हक में हूं कि कीमतों को फ्रीज कर दिया जाय और इसके साथ ही लोगों को सस्ते भाव पर चीज बेची जायं, फिक्स्ड प्राइस पर बेची जाय, सस्ते भाव पर बेची जायं। अगर हम इस तरह का प्रबन्ध कर सकते हैं, तब ही हम इस चीज का इलाज कर सकते हैं।

आपने बेरोजगारी की समस्या के लिए पांच करोड़ रुपया रखा है। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि इस रकम को सही मशीनरी द्वारा खर्च किया जाना चाहिये ताकि जिस चीज के लिए खर्च किया गया है, उससे लोगों को लाभ मिले। अगर उचित चीज पर यह रुपया खर्च नहीं होगा तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और अगर इस तरह से इसका लाभ दूसरे लोगों को हो जायगा। अगर आपको बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, तो ऐसी बात न हो कि जिनको जरूरत है उनको तो इसका लाभ मिले और जिनको जरूरत नहीं उनको इसका लाभ मिल जाय। आज हमारे देश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। मेरे

पास कुछ आंकड़े है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। मैट्रिक की जो फिगर है वह करीब 1,735 लाख के है, अंडर ग्रेजुएट की संख्या 9.32 लाख, है ग्रेजुएट को संख्या 6.2 लाख है और अनुसूचित जातियों की 6.7 लाख है। इस कदर जो हालत है बेरोजगारी की तो यह हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह इस बारे में और भी बात सोचे और साधन निकाले, ज्यादा चीजों पर जोर दे ताकि यह जो समस्या हमारे सामने भयंकर रूप में खड़ी हुई है उसका इलाज हो सके।

एक और बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हम अपने देश में समाजवाद को कभी भी नहीं ला सकते हैं, जब तक ब्यूरोक्रैसी, जो अंग्रेज हम को दे गये है जाते वक्त यह ब्यूरोक्रैसी किसी भी प्लान को चलने नहीं देगी। कभी ऐसा हो सकता है कि समाजवादी प्रोग्राम हो और चलाने वाले लोग ब्यूरोक्रेसी के हों, जिनका समाजवाद पर विश्वास न हो, तो फिर किसी तरह से देश में समाजवाद आ सकता है। मैं यह बात कह कर किसी के ऊपर आक्षेप करना नहीं चाहती हूं। मेरा तो अपना चालीस साल का अनुभव है कि सरकार कोई भी प्रोग्राम तक तब इम्पलीमेंट नहीं कर सकती जब तब वह काम ब्यूरोक्रैसी के हाथ में रहेगा। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां आप बड़ी बड़ी चीजों को ठीक कर रहे है वहां पर ब्यूरोक्रैसी को भी ठीक करने की जरूरत है। आप प्रमोशन बेशक आफिसरों का करें, लेकिन उन लोगों का करें जिनका समाजवाद के ऊपर और इसके सिद्धांत पर विश्वास है। यह नहीं कि प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से हो गया और उन्ही आफिसरों का, आई० सी० एस० आफिसरों का कर दिया जो हमारे कामों में रुकावट डालते हैं। अब उन्हें अपना तरीका और रवैया बदलना होगा। लेकिन जब तक इस तरह की चीज को शासन नहीं बदलती है, तब तक यह चीज नहीं होती है।

हमने बहुत से कार्यक्रम निश्चित किये हैं। हमने शहरों में जो सम्पत्ति है उसके ऊपर सीलिंग लगाने के बारे में बात कही है, यह बात ठीक है कि बहुत से स्टेटों मे यह बात हो गई है, कुछ में कामयाबी हुई और कुछ में नहीं हुई। तो मेरा यह सुझाव है कि यह जो शहरी सम्पत्ति के बारे में सीलिंग लगाने की बात है, यह उतनी ही लगाई जानी चाहिये जितनी आपने गांव को जमीन पर लगाई है। उस गांव की जमीन से जितनी आमदनी होने वाली है यानी जितनी उसकी कीमत है, उतनी कीमत पर शहर में सम्पत्ति होनी चाहिये। अगर आपने इस तरह की बात की तो समानता बनी रहेगी और भेदभाव नहीं रहेगा। जो किसान है वह यह समझेगा कि हमारे साथ पक्षपात करते है, अगर शहर और गांव की जमीन में आपने सीलिंग में भेदभाव किया।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं जो इस हाउस में और उस हाउस में रोज उठती है और वह चीन का मामला है। हमने लोगों से वायदे किये हैं कि हम उनकी भलाई के लिए बहुत से कार्य करेंगे और उनमें चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की भी बात है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि जहां वह बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल कर रही है, वहां पर वह चीनी मिलों का भी राष्ट्रीयकरण कर दे। आज सारे देश में जो हाहाकार चीनी के सम्बन्ध में उठ रहा है, उसकी वजह से सरकार भी बदनाम हो रही है। मुझे पता है कि आज चीनी की देश में कमी नहीं और चीनी की पैदावार भी कम नहीं हुई है। लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति और मिल मालिक बैठे है, ये जानबूझकर चीनी का अभाव पैदा कर दे रहे है ताकि लोगों को तकलीफ पहुंचे; क्योंकि वे नहीं चाहते है कि जो आपके प्रोग्राम है वे सफल हों।

पिछले प्लान में हमने एग्रीकल्चर पर 20.7 परसेंट खर्च किया, लेकिन दूसरे मुल्कों से फिर भी अनाज मंगाना पड़ा। 160 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं जो हम दूसरे सूबों को कर्जे के रूप में दे रहे हैं। 19.7 परसैंट अगर हम सूबों को अधिक दे दें तो हमें बाहर से अनाज न मंगवाना पड़े, अगर पंजाब, हरियाणा को दे दें जो बहुत पैदावार कर रहे है। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार इन सूबों को कुछ मदद दे दे तो अनाज की बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। जितनी हिन्दुस्तान के अन्दर कनक की खपत है उसका 65 परसेंट पंजाब दे रहा है। आप देखिए कितना बड़ा

[श्रीमती सीता देवी]

प्रपोर्शन पंजाब दे रहा है। यह पंजाब जो आपको मदद देता है यह एक किस्म से फारेन एक्सचेंज है। अगर पंजाब इतना न दे तो आपको विदेश से भीख मांगनी पड़े। मैं भीख नहीं मांग रही हूं, मैं वे चीजें चाहती हूं जो पंजाब को मिलनी चाहिए और जिनकी तरफ सेन्ट्रल इरीगेशन मिनिस्टर थोड़ा सीनियेन्ट व्यू ले ले या अपने कर्तव्य का पालन कर लें तो समस्या हल हो सकती है।

हमारे यहां बिजली की बड़ी शार्टेज है। बिजली के बिना ट्यूब वेल नहीं चल सकते। जब ट्यूब वेल नहीं चलेंगे तो खेती नहीं होगी और अनाज नहीं होगा। जो हमारे बहुत बड़े प्राबलम हैं उनके बारे में दो-तीन सजेशन देना चाहती हूं और उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। थीम डेम का प्रपोजल 64 में बना, स्टेजेज में चलता रहा। पिछले साल मीटिंग जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हरियाणा की हुई और यह फैसला किया गया कि जो जो इन्ट पंजाब में इंजीनियर्स की सीनियॉरिटी थी उसी के हिसाब से लगे ताकि यह न हो कि कोई जूनियर आदमी सी.नयर बन जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, मिनिस्टर साहब बीच में बैठे थे। फिर लोक सभा में एक सवाल के जवाब में बताया 27 मार्च को—प्रश्न नं० 483—मैं इसलिए कोट कर रही हूं कि मिनिस्टर साहब देख लें कि मैं गप्प नहीं मार रही, फैक्ट्स कह रही हूं। फिर मिनिस्टर साहब ने बताया कि सरकार कन्सीडर कर रही है और जल्दी ही थीम डेम चल पड़ेगा। पंजाब सरकार ने लिखा कि जब यह फाइनलाइज हो गया, फैसला हो गया कि डेम पर सारा खर्च केन्द्रीय सरकार ने करना है तो हमें इजाजत दी जाय ताकि थीम डेम शुरू हो। 64 के बाद 73 हो गया। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार थोड़ी मदद दे तो बहुत सारा प्राबलम हल हो सकता है।

हमारी बड़ी देर से डिमान्ड है कि पंजाब में एटामिक पावर प्लान्ट जल्द लगाया जाय। उससे हमें बिजली मिलेगी। हमने थर्मल प्लान्ट भटिंडा में लगाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है थर्मल प्लान्ट कोयले से चलता है। पंजाब कोयले की खानों से बहुत दूर है। कहां बिहार और कहां पंजाब। कोयले को लाने में बड़ा खर्च हो जाता है। और इसलिए अगर बिजली बनगी तो बड़ी महंगी बनेगी। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने 13-1-73 को चिट्ठी लिखी कि आप हमें फौरन यह प्लान्ट दे, उसके लिए जगह भी निश्चित कर दी, यह भी लिखा कि एक हजार मेगावाट बिजली पंजाब में इससे पैदा हो सकती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जल्दी दे दे तो यह काम हो सकता है। फिर क्या हुआ, कहा कि नहीं कर रहे हैं। लोक सभा में अन-स्टार्ड क्वैश्चन 604 के उत्तर में 4 अप्रैल को मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह सोच रही है कि जल्दी से जल्दी लगाये और इस काम के ऊपर लगाये। इसको वह आज सोच रही है, आज तक क्यों नहीं सोचा।

फिर पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि सौ मेगावाट बिजली जो कोटा का एटामिक पावर प्लांट है, उससे हमें मिलनी चाहिए। मांग की और लोड सर्वे कमेटी और वर्ल्ड बैंक टीम ने यह फैसला भी कर दिया कि पंजाब को इतनी बिजली दी जाए। पंजाब के बोर्ड ने ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार कर दिया और फरवरी 27, 1970 को पंजाब के एम० पी० मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने यकीन दिलाया कि बिजली आपको मिलेगी। यह 1970 की बात थी, आज 1973 है। फिर 24-12-72 को केन्द्रीय सरकार ने लिखा कि यह अंडर कंसिडरेशन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने टेलीग्राम दी, उसकी कापी मेरे पास है कि 105 मिलियन यूनिट प्रति दिन कोटा से पंजाब को बिजली मिलनी चाहिए। ये तीन इंस्टांसेज मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं कि अगर हमारी केन्द्रीय सरकार इस जगह से हमको बिजली दे देती तो उससे हरियाणा को भी मिले तो अनाज की जो बड़ी प्राबलम है, पंजाब आगे ही ग्रीन रिवोल्यूशन करता है—उससे सारा अनाज पैदा हो जाता। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, सारे देश का स्वार्थ है, पंजाब तो सारे देश का पेट भर सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहती हूं कि वे इरिगेशन मिनिस्टर साहब से कहे कि अगर उनके पास ज्यादा काम है तो इस महकमे को कोई और मिनिस्टर ले ले, खुद प्राइम मिनिस्टर ले ले या वित्त मंत्री साहब

ले ले ताकि ज्यादा काम हो सके। तो मेरी ये सजेशन्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं अगर मान ली गई तो इस देश में समाजवाद आ सकता है। समाजवाद नारों से नहीं आयेगा, अपोजिशन को कहने से नहीं आयेगा, प्रैक्टीकल काम करने से आयेगा, जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर अमल करने से आ सकता है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU). in the Chair].

SHRI BABUBHAI M. CHINAI i (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me some time to speak on this very important Bill, that is, the Finance Bill. Before 1 come to the Finance Bill, I would like to say a few words about the state of the economy. Such an exercise, I think, is necessary because the Finance Bill itself has to be framed in that context.

It is unfortunate that when the country and the people were expecting an era of prosperity, today we find that there is acute shortage of almost all essential commodities. Food, the most crucial consumer item, is not readily available even for love of money. This has resulted in riots in a number of places. Power, cloth, cement, paper, bricks, sugar, vanaspati. kerosene, edible oil, in fact almost every essential commodity is scarce. As a result, prices of these commodities have been rising at a very stupendous rate.

In the last one year the general price level has been going up at the rate of more than one per cent per month. The situation has been further aggravated bv the fact that the number of unemployed has been rising very rapidjy. For example, the number of applicants on live registers of employment exchanges at the end of December, 1972 was 6.9 million, compared to 5.1 million a year back. All in all, it looks that the economy has seriously run down and unless efforts are made to increase production and investment rapidly, both in the public and private sectors, we I may be faced with an unprecedented ciisis. This must be anyhow avoided. It is in this background that I submit that Government must seriously consider jwhether their present fiscal and economic policies and the current programme of taking over the distributive trade are really effective instruments eirher for economic growth or social welfare.

Coming to the Finance Bill let me first thank the Finance Minister for the amendment to the Finance Bill allowing a deduction of tax levied by the State Governments on the agricultural income in computing the agricultural income to be integrated with non-agricultural income for taxation purposes. I am, however, of the view that this solves the problem only partially. Those in agricultural income-tax levying States would continue bearing a heavier load of tax incidence on their combined agricultural and non-agricultural income than those in other States. For example, tax liability for a person with a total income of Rs. 1,20,000/- comprising Ks. 1.00,000/- from non-agricultural income and Rs. 20.000 from agricultural income would compute to Rs. 73,600/- if he is in a State which does not levy agricultural income-tax. However, if he happens to be in a State levying, say 30 per cent agricultural income-tax, his tax liability, if computed in accordance with the Finance Minister's amendment, would go u_f to Rs. 76,070/-. being Rs. 70,070/-Central income-tax on non-agricultural income and Rs. 6.000/- Stale agricultural income-tax. I am sure the learned Members of the House will appreciate that this is not fair. I. therefore, submit that State agricultural levies, instead of being allowed deduction from the agricultural income, should be allowed deduction from the tax liability on the combined agricultural and non-agricultural income.

It is also unfortunate that, while, on the one hand, the recommendation of the Wanchoo Committee in regard to a separate rate schedule for income-tax and wealth-tax resulting in a sharp increase of tax incidence has been introduced for

[Shri Babubhai M. Ciiinai.] Hindu undivided families, the recommendation of the Wanchoo Committee with regard to the general lowering of the maximum marginal rate of income-tax has been altogether ignored. I take this opportunity to stress the need for bringing down the maximum marginal rate of income-tax and wealth-tax to reasonable levels, if the incidence of tax has not to stifle the initiative and incentive to work and to voluntarily comply with tax laws.

I also fail to understand the reason wny surcharge on income-tax payable by companies should stand on the statute when all other Bangladesh relief levies have been withdrawn. After all, this levy was as much a Bangladesh refugee relief levy and introduced during the war-time as others. I only want to emphasise that emergency levies should be withdrawn immediately after the emergency is over. This not only maintains the public confidence but also keeps the much needed leeway for suitable and swift action in an emergency.

Another important matter which I want to point out is about the withdrawal of tax concession in respect of sums paid under contract for deferred annuity containing a provision for the exercise by the insured of an opinion to receive cash payment in lieu of the payment of annuity.

This measure may cause unintended hardships to a number of cases particularly the self-employed middle class persons who want to ensure a specific amount handy at the time of their retirement. With a view to meeting such cases, I submit for the consideration of the hon. Finance Minister laying down a certain limit, say, up to IVs. 2 lakhs in respect of which tax benefit should continue in spite of cash option. Besides, the proposed provision has to be effective for the assessment year commencing on 1st April, 1974. This will obviouslv cause hardships to those who have taken out policies before 28th February, 1973, and are liable for assessment vear in 1974-75. Such assessees will be deprived of the tax benefit which, in my view, is not equitous. 1 therefore urge thai the new provision apply only to policies taken out after 28th February, 1973.

The Finance Minister has sought to amend the definition of the term 'short-term capital asset' so that a capital asset held bv a person for not more than 60 months immediately preceding the date of its transfer will be treated as a short-term capital asset and the gains arising on sale or transfer of such asset will be taxed as ordinary income. In my view, subjecting to tax, in one year, at sharply progressive rates of tax, gains developing over a ptriod of five years, is not fair. Such gains *t.re* mere artificial gains reflecting the fall in the value of money. Most countries treat assets held beyond six months to two years as long-term capital assets and the g;iins arising therefrom are either totally exempt from tax or are taxed at concessional rates. I am therefore not in favour of increasing the period of holding an asset from 24 months to 60 months for an asset to qualify as long-held asset. However, if a change in this respect is deemed necessary, I suggest that the basis of taxation of capital gains may be so rationalised that the capital gains arising from transfer of assets are taxed at the rates which have some relation to the period during which the asset is held. In this regard I also want to point out that the provision as proposed will be effective from the 1st of April, 1974, and would thus cause avoidable hardship to those who effected transfer of capital assets before 28th February, 1973, and as per their previous year are liable to tax for assessment in respect of the transfer in assessment year 1974-75. Such assessees, it may be appreciated, could not foresee the ch;,nge to take the tax element into account while effecting the transfer. I therefore submit that it will be equitable if it is provided that the provision shall not apply to transfers effected prior to 28th February, 1973.

1 also do not see any justification In taxing the amount received as compensation for taking over management of any

business by Government. It has to be appreciated that management is taken over by Government not at the volition of the assessee. Besides the assessee may have to incur a variety of expenses out of the compensation received. Subjecting the compensation money to tax as income from profits and gains of business is, therefore, in my view, not equitable. The amount being in the nature of capital receipt should be excluded from the purview of tax. If, however, the management compensation is to be taxed, it should at least be treated on par with compensation for termination of managing agency. That is, 25 per cent of the compensation money should be allowed deduction for computing the taxable income as in section 80 S of the Income-tax Act.

May I also say a word about the initial depreciation allowance likely to be proposed soon as an alternative to the development rebate? It has been stated by the Finance Minister that it would be applicable only in respect of selected industries. In my view, since the development rebate was available to all industries, initial depreciation should also be made available to all industries.

I ssggest that at least for priority Industries and industries in backward areas, some additional depreciation allowance is essential.

i

I welcome the proposal of the Finance Minister to give incentive to development of backward areas. However, I feel that this benefit will be extremely limited in scope and the advantage of the incentive will not be available to all regions where j development has to be fostered. 1 would suggest that the definition of "backward area" should be liberal enough to make all regions benefit from the scheme.

Lastly, let me now say a few words about indirect taxation. I would emphasise that the 40 per cent import duty on cotton is unrealistic and prohibitive. Already the mills are increasingly using indigenous ', cotton. This is good so far as it goes, I but it does not enable the smaller people to get yarn at reasonable prices, nor do the consumers get cloth anywhere near fair prices. The sharp spurt in the price of textiles since August last is unprecedented in the history of India.

The Yarn Control Order is also contributing to the rise in prices. Although the Central Government has not asked the Slate Governments to oust the normal trade, the latter have done so, with the result that the smaller weavers are not getting yarn at all.

I am glad that the Finance Minislei has already announced some concession in the Customs duty on black and white "raw-cinematograph films reducing it frorr 50 to 30 paise per linear metre. However, 1 have been informed that even a dut> of 30 paise per linear metre will be too heavy a burden for the film industry to bear. Further, a 5 per cent *ad valorem* auxiliary Customs duty will also have to be paid. Even now the film industry is going through a period of strains and stresses. Many of the producers who were once investing lakhs and lakhs of money on a film have now started economising in their investment. This is mainly because, on the one hand, the cost of production has gone up and on the other due to keen competition. they are not getting adequate return on investment. They have not only to pay huge amounts to the stars but also to the studios and the distributors. I, therefore, strongly urge that the recent increase in import duty on raw cinematograph films should be completely withdrawn.

The policies followed by the State and Central Governments are unco-ordinated. Distribution of yarn, and distribution of wheat and rice are the recent examples. While it is said that the Central Government would want only the take-over of wholesale trade in wheat and rice, some State Governments have already disrupted the retail trade also, for example, in the city of Bombay. Thank you.

[Shri Babti Bhai M. Chinai]

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): It is a good augury, Mr. Vice-Chairman, Sir, that our Finance Minister is physically present to-day to listen to this debate. I hope, after listening to the debate, he will in his reply show some concessions to the suffering masses. Sir, after the presentation of the Budget, the prices of foodgrains, edible oils and other bare necessities of life have risen, up to now, by 25 to 27 per cent. This is not a tall statement that I am making without any basis. I would ask the hon. Finance Minister to depute a trustworthy man, a man who is in his confidence, to go to ;<ny bazar, in Delhi or in any other place. and find out to what extent the prices have si ot up. The price of everything has shot up. And if at all there is anything cheap, it is, I am sorry to say, corruption. Corruption is the cheapest commodity now in the country. It may surprise you, Sir, to think how people are living in this country. A man who was spending Rs. 25 on groceries six months before has to spend now Rs. 80. What is the increase that he has got in his emoluments? Not even a pittance of five rupees. And how do you hope that the ordinary people will get along? The prices of foodgrains, oil, vegetables, everything has gone up. The Finance Minister said the other day that he had, for the good of the country, levied excise duty on cigarettes, tobacco, etc., etc. But finally the whole thing comes on the head of the common man. Now cigarettes and tobacco are taxed but nobody in our country is a saint.

I believe even our Finance Minister smokes and he has to pay and he can afford to pay....

SHRI MAHAVIR TYAGI: No, he does not smoke.

SHRI S. S. MARISWAMY: But what about the rest of the people? If you go to any workshop, any coal-mine—unfortunately Mr. Kalyan Roy is not here; he can tell us about coal-mines—any factory, you will find that people, whenever they get hungry, take more of tea or cigarettes or beedis. It quenches their huncer. Invariably everyone of them goes either for tea or for a cigarette or a beedi in order to quench his hunger. This has become a fashion. So, by levying these taxes you are not helping the poor. If you tax cigarettes and other things, then certainly this tax is going to fall on the common man.

Then about unemployment. No serious attempt has been made to solve the unemployment problem. In 1971 the figure was 45 lakhs. In 1972 the figure of unemployed people rose to 57 lakhs. And now, I understand, it is more than 1 crore odd. And what is it that the Government is going to do? Unfortunately we have witnessed today food riots in Nagpur which is a part of the Finance Minister's State. In his neighbouring State, Gujarat, also there was a food riot. I heard some stories from Nagpur. The stories were horrible. I really shudder to think as to what is going to happen to this country if similar things happen in all parts of the country and if no drastic measure is taken to solve the sufferings of the people. An entire family, the mother, the father, the children and all other dependents, have to go and stand in queue in front of the ration shops tc get their rations and unless and until they do so, they are not given their ration. And what is the quantum of the ration they get? Four ounces of wheat is given I'er head per week. Now, how can you expect people to live with four ounces of wheat a week? In Madias in 1952 siv ounces of rice were given. That was a slogan to bring down the Congress. In those days if any man walked on the road wearing khadi, people used to heckle him saying, "Oh I six ounces, you are going". That slogan alone brought down the Congress rule in that State. After all your so-called green revolution, after all your trumpeting that you have achieved self-sufficiency, with yotir slogan of *garibi iiatao,* after the so-called dynamic Ministry has come into power, what have you achieved? Now people have to go and si and in queue for four ounces of wheat per head per week in Nagpur and other places. And by the time half the queue is

linished, you declare stocks are exhausted ana you start closing the shutters. In this situation if people naturally get agitated, helpless, and if there is disturbance, immediately you call the police and lathi charge is done. This is what happened zctually at that place. I am subject to cor- iection. This is what I heard. In the lathi charge and police firing many precious lives were lost. 1 cannot understand why a country, after 25 years of independence. still depends for foodgrains upon foreign imports. It is a shame. This Government has thoroughly failed. I do not blame our I Finance Minister. I know he is a good | man. But what is the entire Cabinet doing? Where have our Plans gone? If the people j cannot get two morsels of food, then there is absolutely no use of this Government existing. There is anarchy. *(Interruption)* You are going to bring a chaotic condition and I do not know where it is going to -lead to. This situation is a very alarming situation. I want the Finance Minister to bestow his immediate attention on this problem. Secondly, about educated unemployed. That figure also is very high. In 1971 the figure of educated unemployed was 27 lakhs. Now it is 60 lakhs. It is like giving a knife in the hands of a child, letting loose the educated unemployed in the country. A child does not know how dangerous it is to play with a weapon. In the same manner, if the educated people are not given jobs, they will sit and co on thinking which may lead to many undesirable things. Many revolutions have been started by the educated unemployed people.

I may not get surprised if something happens in the country and the wind is also blowing in that direction. After what bas happened in the Supreme Court, I doubt very much whether we have any orderly system in the country. For example, today I was really shocked when I read a news item. I did not know whether I was in' India' or in Romania or, for that matter, in some other country. This is today's Hindustan Times edited by a pro-Congress Editor and owned by a group which supports Congress. Workers can 'wrest' favourable verdicts. This is double column heading given to the news item. I will read the relevant portion.

"'Addressing the workers of the INTUC-led Rashtriya Mill Mazdoor Sangh here (that is, Bombay), he said, (that is, Mr. Shankar Dayal Sharma)...

AN HON. MEMBER: He is a Doctor.

SHRI S. S. MARISWAMY: I stand corrected. Dr. Shankar Dayal Sharma said:

"If the wo'rkers are well organised, no judge will dare to give an anti-labour decision in future". (The word 'dare' is to be underlined).

Is it right for the Congress President, the head of the Congress organisation nursed by Mahatma Gandhi who was the apostle of truth and who believed in nonviolence. ..

SHRI BIPINPAL DAS: Mahatma Gandhi used stronger words.

SHRI S. S. MARISWAMY: I do not know what you are referring to. I have also read Gandhiji and I also followed him until his death. He never said in this way.

"Dr. Sharma referred to the preventing of some advocates from attending the Supreme Court on May 3 when the Bar Association observed the bar "solidarity day" and remarked "the workers can also prevent the counsel of the employer from attending the court".

He wants the workers to enter into the court, find out who is going to appear for the employer, catch hold of him and gherao him or assault him or God knows what he wants to be done to him. He is a Doctor and so he knows what. He goes on further:

"In such an event (that is, when the workers catch hold of that lawyer), the Police should not intervene when the Advocates were obstructed while proceeding to the Supreme Court".

Then he goes on in his own way....

AN HON. MEMBER: The Advocates of whom you talk have taught them how to get hold of a Judge and push him out of the Chamber.

SHRI S. S. MARISWAMY: One wrong does not justify another wrong. There the Advocates have done something. Here. Dr. Sharma is asking workers to eo to the court and prevent the lawyer appearing for the employer from appearing. Dr. Sharma is the leader of a responsible organisation of the ruling party. And he speaks like an ordinary soap-box orator and an ordinary third-rate politician. He is the man under whom our Chavan is working. Does he accept him as his leader?

I am really amazed that things are happening in a manner that is not at all good to the country.

For example, this is a book written by a reputed journalist, Shri A. G. Noorani. T believe he hails from Bombay and that the Finance Minister knows him. He is a good writer. He has written a book and this is an article wherein he has brought out a secret document written by my good friend, Shri Kumaramangalam in 1964.

In his 64-page thesis he says like this:

"The bourgeoisie yet heads the Indian National Congress which was the organisation of the United National Front that led the struggle for Indian freedom. Supporting the Congress even today are large sections of the petty bourgeoisie, the major part of the working class. These sections follow the bourgeoisie Congress leadership, not because they support that leadership's real programme of developing capitalism in India, but because they are supporters of the proclaimed programme of the Congress—the Jaipur, Avadi and Bhu-baneswar decisions of the Congress to build 'socialism'."

Then. Sir, he goes on to say:

"The Communist Party would be ready to support the Congress and even to participate in a United National Government if the Congress would implement its own proclaimed policy, and the Communists would join all democratic elements to build a mighty mass movement . . . ."

Then, about the transfer of power on the 15th August, 1947:

"On August 15, 1947, power was transferred from the British imperialists to the representatives of the National United Front, namely, the bourgeois leadership of the Indian National Congress."

That is power was transferred to nobody else but to Shri Jawaharlal Nehru, the acclaimed leader of the 'Indian capitalist bourgeoisie section'. Then. Sir, he goes on saying . ..

SHRI BIPINPAL DAS: Sir. on a point of order.

SHRI S. S. MARISWAMY: Please wait. I am coming to the subject.

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, I want to raise a point of order.

SHRI S. S. MARISWAMY: Please wait a minute. I am coming to the point.

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, what relation has it got with the Finance Bill?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): He is entitled to say that on the Finance Bill. You better read the Rules.

SHRI S. S. MARISWAMY: Then he goes on to say, Sir, like this: "Use the Congress to share its power and then oust it". He goes on to say, "in the last analysis, the decisive force can only be the Communist Party."

Sir, Shri Kumaramangalam might have Joined the Congress. But I wonder whether he has changed his view. I do not know whether he joined the Congress as a tactical measure or with a genuine desire to serve Indiraji... *(Interruptions)* And Sir, the CPI supports the Congress, Sir, there is a quotation of Lenin: "I support such things as the rope supports a man who is being hanged". This is what is being done, what is happening, to get the support of Shri Mohan Kumaramangalam. 'The Supreme Court case is one step. Now, Shri Shankar Dayal Sharma, the Doctor, has given a call to the labour section to wrest favourable verdicts. I really shudder to think as to what is happening in this country. Is there any meaning in retaining the emblems bearing the words "Satya-meva Jayate", the Ashoka Pillar and other symbols all over the country? You can in one sentence say: "Look. This is our Constitution". Or, you can say, "We have no Constitution. Our Constitution is whatever Mr. Kumaramangalam says or Mr. Gokhale says or whatever this man says or that man says". You can make it clear. We have got a Constitution. Whenever it suits you, you quote the Constitution. Whenever it suits you, you say that the Constitution should be respected. Otherwise, you do not wsrry about the Constitution. This sort of double standards must come to an end. [know Mr. Chavan belongs to the older section of the Congress who has done yeoman's service to the cause of freedom and I know, if contacted privately, he will condemn Dr. Sharma's views. But he cannot open his mouth now because himself and other nationalist elements in the Congress are prisoners in the hands of Mr. Kumaramangalam and other people.

Sir, a day will come—take it from me—when all these Ministers would find it difficult to speak to their own Secretaries. If they want to speak to their Secretaries and pass some orders, it will have to be routed through Mr. Kumaramangalam or Mr. Gokhale and that day is not far off. We have seen what happened in Eastern Europe soon after the War. The Communists joined hands with all the parties even

16 RSS/73—8.

of the capitalists, and as Mr. Kumaramangalam has said, in the last analysis, everybody would disappear and the Communists alone will be there like the Gundhara about whom we have read in our mythology.

Sir, I hope I have driven home the point and that the Government will consider them and do something about them. Thank you, Sir.

कमलनाथ झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में आज मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और बोलने से पहले जब मेरी दृष्टि घड़ी की ओर जा रही है तो मैं देखता हूं कि पांच बजने में सिर्फ दस मिनट ही बाकी है . . .

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : हम 6 बजे तक बैठेंगे।

श्री कमलनाथ झा : जब कभी अपने देश में राजनीति करवट लेती है तो उस की कुछ प्रतिक्रिया तो होती है। यह प्रतिक्रिया आज ही नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि हिन्दुस्तान की आधुनिक राजनीति की जब से शुरुआत हुई है उस समय से ही यह प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। जब कांग्रेस को हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता ने एक क्रान्तिकारी मार्ग पर अग्रसर किया तो चाहे वह वामपंथी हों या दक्षिण पंथी, दोनों तरह के लोगों ने कहा था कि वे इस देश को रसातल में पहुंचा देंगे। जब 1942 की महाक्रांति हुई और अंग्रेजी हकूमत से हिन्दुस्तान की जनशक्ति टकरायी तो जितने बुद्धिजीवी थे हमारे एक कदम पीछे हटने पर, उन्होंने कहा कि गांधी जी और जवाहरलाल जी ने देश को सौ कदम पीछे हटा दिया। लेकिन बाद में इन लोगों ने देखा कि 1947 की रात 12 बजे दिल्ली के सिंहासन पर से यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसके स्थान पर तिरंगा लहराने लगा। जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की बैठक हुई तो जो स्वराज्य जनता की मदद से प्राप्त किया गया था उसको जनता तक

[श्री कमलनाथ झा]

ले जाने के लिए हमारे तत्कालीन नेताओं ने घोषणा की कि जनता के बल पर हमें राजसत्ता प्राप्त हुई है और बालिग मताधिकार द्वारा हम जनता को सत्ता सौंप देंगे। इस पालियामेंटरी डिमोक्रेसी को इंगलैंड ने जन्म दिया वहां के क्रांतिकारियों और वहां के मानवतावादियों को भी इतना साहस नहीं हुआ कि वे यूनिवर्सल सफरेज का एलान करते और आज से केवल पांच साल पहले वहां महिलाओं को बालिग मताधिकार दिया गया है। लेकिन हमने जिस दिन कांस्टीट्यूशन लिखना शुरू किया उसी दिन हिन्दुस्तान के तामाम बालिगों को चाहे वह पढ़ें हों या अनपढ़ हों, चाहे वह द्विज हों या शूद्र हों, चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान, हमने सभी को बालिग मताधिकार दिया। नयी करवट ली हिन्दुस्तान की राजनीति ने और इस अवसर पर भी बड़े-बड़े विद्वानों ने, बड़े लोगों ने और बड़े समाज चिन्तकों ने कहा कि ऐसी डेमोक्रेसी से हिन्दुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हिन्दुस्तान की सरकार नहीं चल सकेगी, लेकिन हमारे जनतंत्र की भी परीक्षा हुई सब्जेक्टिव एवं आब्जेक्टिव विदेशियों ने आक्रमण किया, चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। यह हमारी पोलिटिकल कांसेस-नेस थी और जब देश में लोगों ने हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश की तो हमारे जनतंत्र ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी इस देश के टुकड़े नहीं कर सकता है। हिन्दुस्तान के 50 करोड़ लोग इसके प्रहरी हैं। आज हिन्दुस्तान में शक्तिशाली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्यों में स्टेबिल सरकारें हैं। हमारी सरकारें जनता के वरडिक्ट पर खड़ी हुई हैं। फिर तीसरी करवट हिन्दुस्तान की राजनीति ने ली। प्रति-क्रियावादी शक्ति से प्रगतिशील शक्तियों का टकराव हुआ। नई शक्ति उभर कर सामने आई। करांची कांग्रेस से लेकर बम्बई कांग्रेस तक की यात्रा में जनता को जो आर्थिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय देने का वायदा किया गया था। हमने उसको अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया है और वह है गरीबी मिटाना। आज फिर जिस तरह से हमारी आजादी की लड़ाई का मखौल उड़ाया गया था, जिस तरह से जनतंत्र की स्थापना का बालिग मताधिकार का, मखौल उड़ाया गया था, उसी तरह से एक बार फिर हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसैल्फ बट आन दि अदर प्लेन, लोग गरीबी मिटाने की लड़ाई का मखौल उड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक हमारा मखौल उड़ाया था, इतिहास ने अब तक उनका मखौल उड़ाया है और हमें विश्वास है कि इतिहास फिर एक बार उनका मखौल उड़ायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जनतांत्रिक ढंग से, पालियामेंटरी ढंग से, डेमोक्रेटिक तरीके से, सोशलिज्म की ओर बढ़ रहा है। गरीबी तो हटेगी। बुनियादी सवाल है कि कैसे हटेगी? इंगलैंड ने इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन किया, जर्मनी ने इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन किया, फ्रांस ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया। कैपिटल फार्मेशन कहां से हुआ। इन देशों में कैपिटल फार्मेशन इसलिए हुआ कि संसार के बड़े भूभाग को इन्होंने दबोचा। उपनिवेश बनाया और वहां से रा-मैटेरियल इकट्ठा किया और जब इससे भी काम नहीं चला तो आजादी की लड़ाई के वक्त में हमने पढ़ा "अवध के नवाब के घर में किसने डाका रात को डाला था और वाजिद अली शाह के घर का तोड़ा किसने ताला था", हमारी दौलत कालोनियल सिस्टम से लूटी गई और जब इससे भी काम नहीं हुआ तो रानी एलिजाबेथ के रेन में हाकिन्स और ड्रैक ने हाई-सीज में लूट-पाट की। इतिहास जानता है कि अमेरिका ने किस तरह से स्लेव्स लेबर का एक्सप्लायटेशन कर के कैपिटल फार्मेशन किया। जो डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट के देश हैं, चीन और रूस, उसमें व्हाइट-टेरर एंड रेड-टेरर की बात इतिहास अभी तक भूला नहीं है। लेकिन न हम स्लेव का एक्स-प्लायटेशन चाहते हैं, न हम उपनिवेशवाद चाहते हैं, न हाई-सीज में एलिजाबैथ के सी-डाग्स की तरह लूट करना चाहते हैं और न डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट की तरह से मनुष्य को यंत्र बना कर कैपिटल फार्मेशन करना चाहते हैं, बल्कि मानवता की रक्षा करते हुए, मानव स्व-

स्वतंत्रता की रक्षा करते हुये, कठिनाइयों से झूझते हुये हम अपने कैपिटल फार्मेशन का एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। आज अगर थोड़ी सी मूल्य में वृद्धि हो जाती है...

श्री ना० कृ० शेजवलकर : थोड़ी सी ?

श्री कमलनाथ झा : अच्छा, अधिक ही मूल्य बढ़ जाता है। अगर मूल्य बढ़ जाता है तो वह इसलिए कि हम 50 करोड़ आदमियों को सुख पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग प्रगति चाहते हैं, लेकिन प्रगति के लिये परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं। परेशानी उठाये बिना प्रगति असंभव है। अगर हम प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपये की पूंजी इनवेस्ट करेंगे तब कहीं लोगों की कुल आमदनी चार सौ रुपया या पांच सौ रुपया या तीन सौ रुपया प्रति माह होगी। करोड़ आदमियों के लिए इतनी आमदनी, इतनी इनकम कहां से लायेंगे, जब तक कि बड़ी तादाद में हम कैपिटल इनवेस्ट नहीं करेंगे। आज संसार में जो पूंजी के ठेकेदार हैं, वह कहते हैं कि तुम हमसे पूंजी लो लेकिन तुम अपनी आजादी हमारे पास गिरवी रखो। हमने खून की कीमत से आजादी पाई है, हम उसको रुपये की कीमत पर गिरवी रखना नहीं चाहते, हम अपनी जनता को जानवर भी नहीं बनाना चाहते (डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरियट) तो बताइये कैपिटल फार्मेशन कैसे होगा ? गरीबी कोई नारे से नहीं हटेगी। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। इसका एक ही वे-आउट है। अगर हम कष्ट नहीं उठायेंगे, अगर हम टैक्सेशन नहीं करें, अगर हम अपनी बेल्ट को टाइट नहीं करें, तो संसार में कौन है जो कि कुबेर का खजाना ला कर हिन्दुस्तान को बांट देगा और उस खजाने से हम अपनी गरीब जनता की आमदनी 200, 300 या 400 रुपये की कर लेंगे, इतनी मिनिमम इनकम हम एश्योर करेंगे।

5 P. M.

इसलिए हिन्दुस्तान को अपने इन्टर्नल रिसोर्सेज के बल पर, जनता की मेहनत के बल पर अपनी खुशहाली की इमारत खड़ी करनी होगी। मैं सुन रहा था, एक मेरे मित्र कहते थे कि अमेरिका भारत को चेन आफ फर्टिलाइजर फैक्टरी दे रहा था। एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, अभी वह संगठन कांग्रेस में चले गये हैं, वे कहते थे कि पी० एल० 480 में जब सस्ता गेहूं मिल रहा है तो हिन्दुस्तान में गेहूं पैदा करने की जरूरत क्या है ? हिन्दुस्तान पी० एल० 480 में गेहूं ले आये, भोजन और भोजन की पैदावार के लिए अमेरिका या अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहे तो हिन्दुस्तान आजाद रहेगा या गुलाम होगा ? यह हमारा हिन्दुस्तान होगा या खाना देने वालों का हिन्दुस्तान होगा ? इसलिए हम पूंजीवादी एवं तानाशाही दोनों मार्गों के विरोधी हैं। न हम पूंजीवादी रास्ते से दूसरे के खून को चूस कर, दूसरों को गुलाम बना कर अपनी इमारत खड़ी करना चाहते हैं और न अपनी जनता को बेड़ियों में कस कर, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल कर समाजवाद बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, हमारा एक अभिनव प्रयोग है। क्या होगा, हम नहीं जानते। हमको गीता के उस श्लोक की तरह—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन—एक अभिनव प्रयोग करना है, जिसमें डेमोक्रेसी भी हो, जिसमें सोशलिज्म भी हो। ऐसा प्रयोग आज तक संसार में कहीं नहीं हुआ। इसलिए हम अपने मित्रों से कहते हैं, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है, अगर आपको हिन्दुस्तान से प्रेम है, अगर आपको डेमोक्रेसी से प्रेम है, अगर आपको गरीबों से हमदर्दी है तो आपको हमें सहयोग देना चाहिए। इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो आप याद रखें हिन्दुस्तान की गरीब जनता अपनी गरीबी तो मिटाएगी, लेकिन आने वाले इतिहास में आपका नाम उसी लिस्ट में लिखा जायेगा जिस लिस्ट में आजादी की लड़ाई का विरोध करने वालों का लिखा गया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन चंद प्रारंभिक शब्दों के साथ आपके माध्यम से अपने माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक विशेष समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आखिर आजादी के पच्चीस वर्षों में, इस स्वराज्य के पच्चीस वर्षों में, जो समाज का स्वरूप आज तक खड़ा हुआ था उसके खिलाफ बगावत करके हमने एक नए

[श्री कमलनाथ झा]

मार्ग का अनुसरण किया है। वह मार्ग है देश से गरीबी मिटाने का मार्ग। यह गरीबी दरअसल है कहां पर? इट मस्ट बी लोकेटेड फर्स्ट। इसको पकड़ना होगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हुआ। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को भी कठिनाई है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते, कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि उसके लिए कुछ नहीं हुआ। आज बड़े-बड़े और माध्यम काश्तारों को भी कठिनाई है, उचित दाम नहीं मिलता है, लेकिन सरकार ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन एक तबका है हिन्दुस्तान में और वह सबसे बड़ा तबका है। वह सबसे गरीब है और मैं समझता हूं कि उसकी ही गरीबी से प्रभावित होकर श्रीमती इन्दिरा गांधी और आदरणीय नेता चव्हाण ने कांग्रेस में भी अगर टूट करने की जरूरत पड़ी तो किया और वह है हिन्दुस्तान के गांवों में बसने वाले 17 करोड़ खेतिहर मजदूर। आज जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए हमने सिक्योरिटी आफ सर्विस दी है, उनकी नौकरी कोई छीन नहीं सकते हैं। नम्बर 2, उनको बोनस दिया, 4 परसेन्ट के बदले 8 परसेन्ट, आपके यहां लास भी हो तो। काम करने के समय अगर उनकी अंगुली कट जाए तो वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट उनके लिए बनाया गया है, वे रिटायर करें तो ग्रैचुइटी और प्राविडेन्ट फण्ड की फैसिलिटी उन्हें दी गई है और अगर व बीमार पड़ जाएं तो एम्प्लायीज स्टेट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की मार्फत उनके पीछे 5,000 रु० भी खर्च करना पड़े तो किया जाएगा। यह सब होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। लेकिन वह मजदूर जो गांवों में काम करता है, खेतिहर मजदूर, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है? आसाढ़ में चिलचिलाती धूप और भादों में उमड़ते हुए आसमान के नीचे वे काम करते हैं। लेकिन उसके लिए कोई एम्प्लायमेंट की गारंटी नहीं। वे छः महीने काम करते हैं और छः महीने बेकार रहते हैं। उनके लिए आज तक इम्प्लाइज स्टेट इश्योरेंस कारपोरेशन की स्कीम नहीं है तथा उसको इन 25 वर्षों में सल्फागुलाइडिन और इन्ट्रोकिनोल जैसी साधारण दवा तक नहीं मिल सकी। उनके लिए आज तक प्राविडेन्ड फंड की व्यवस्था नहीं की गई और न ही पेंशन की कोई गुंजाइश की गई। सारे भारत में आज किसानों का नाम लिया जाता है, लेकिन खेती में जो कमौनी करता है, जो रोपा करता है, जो कटनी करता है, जो उसावन करता है, उसको किसान नहीं कहा जाता है, बल्कि जो सुपरवाइजर है उसको किसान कहा जाता है। जो वास्तविक खेती करते हैं उन्हें किसान न कह कर किसान उन्हें कहा जाता है जो खेतों में काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों ने गरीबी को हटाने का जो व्रत लिया है, जो उसके लिए प्रोग्राम बनाया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी जी यह कहा करते थे कि अगर देश के लिए कोई योजना बनानी हो तो हिन्दुस्तान के सबसे अधिक गरीब आदमियों को सामने रख कर योजना बनाई जानी चाहिए। हम अब पांचवीं योजना तैयार करने जा रहे हैं और इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस दृष्टिकोण को उन्हें अपने सामने रखना चाहिए। मैं अपने क्रान्तिकारी वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य में और केन्द्रीय स्तर पर भी एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए जिन के जिम्मे केवल खेतिहर मजदूरों का ही विभाग हो। जिस तरह से ट्रेड यूनियनों का एक आर्गनाइज्ड सेक्टर है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल लेबर्स को अधिकार दिये गये हैं, उसी तरह से खेतिहर मजदूरों को भी अधिकार मिलने चाहिएं।

सब विरोधी पार्टियां कहती हैं कि हमारी हमदर्दी खेत मजदूरों के साथ है। मैं आपके सामने बिहार के आंकड़े रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की कुल आमदनी 110 करोड़ रुपया है और यह सब सरकारी कर्मचारियों पर खर्च हो जाती है। इस तरह से सरकार की जितनी भी आमदनी है उसके बेनीफिसियरीज करीब 25, 35 प्रतिशत

लोग ही हैं। आज हमारे यहां जो हरिजन है, आदिवासी हैं, और पिछड़ी हुई जाति के लोग है, उनको आम तौर पर फायदा नहीं हुआ है। इसके जो लीडर हैं, जो नेता लोग हैं और जो कुछ और होशियार लोग हैं उनको भले ही फायदा हुआ है और मासेज पिछड़ी हुई ही हैं। जाति के नाम पर समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने का पुराना तरीका बकार सिद्ध हुआ है इसमें व्यक्ति विशेष को लाभ होता है और समाज जहां का तहां रह जाता है। अतः, सम्पूर्ण हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़ी जातियों का एक हिस्सा जो पेशे से खेत मजदूर हैं उनको पैसे के आधार पर संगठित करना उनकी रोजी रोटी एवं सामाजिक उत्थान का नवीन अभियान आरंभ करना 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपने घोषित लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, while supporting the Bill introduced by Mr. Chavan to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1973-74, as passed by the Lok Sabha, I should like to bring to the notice of the Finance Minister the clubbing of Central income-tax with agricultural income. Agriculture income varies from State to State and some of the States have already levied a heavy taxation. As far as Kerala is concerned, a fanner who has got a gross agricultural income of Rs. 5,000 is being taxed, whereas in some of the States to the extent of Rs. 20,000 they have been exempted. As far as Kerala is concerned, a farmer who has got an income of Rs. 5,000 is exempted, but if he has got an income of Rs. 5,100 then he has to pay agricultural income-tax and it also goes by the slab system, and a stage comes that a farmer has to give 60 per cent of agricultural income-tax. Apart from this, he has to pay the plantation tax. land revenue and also as far as Kerala is concerned, if a farmer grows paddy, wheat or cholam, whatever it may be, his income comes Into the picture and he is being levied. A small farmer who has got an income of Rs. 10,000, if he happens to have a non-agricultural income somewhere, then both the incomes will be clubbed together and he will be taxed heavily. If that is so, rural economy will be effected, and the rural people who are just coming up with scientific cultivation, modernisation of agriculture now, they have also been taxed very heavily. Of course, the Finance Minister was good enough to make some remissions, but that is not enough. As far as agricultural income is "concerned, that should not be left to the Central income-tax, it should be left to the State concerned, the State should levy it.

Another point is, I am glad that the Government's attention has been paid to the uplift of the backward regions. Special attention is being paid and I welcome that move. At the same time, I draw the attention of the Government to the imbalances of the different communities. I am referring to the Muslim community, a minority community. They do not get into services, they do not get a fair play in the different walks of life. In this connection, I draw the attention of the Government to the illustrated Weekly of India of April 22, 1973 which has recently published an article. I read from page 8—

"As a test-case, let us take the simple but vital matter of jobs under the Government. There is no doubt that unemployment afflicts all sections of Indian society. The poor among the Hindu majority are not much better off than most Muslims; they are perhaps in a far worse position than the off-spring of rich and influential Muslims with right connections and the necessary pull."

But when all is said and done, there can be no escape from the stark reality that the share of the Muslims in public employment is abysmally low. Up-to-date figures arc, alas, not available. But it does seem shocking that, in 1965,

[Shri Hamid Ali Schamnad]

there should have been only 111 Muslims out of more than 2100 IAS officers; around a dozen Muslims out of 270 members of the Indian Foreign Service; and a mere 43 Muslim officers out of 1,200 in the Indian Police Service ! It is doubtful if the position is very much better today because, in 1972, only one Muslim—precisely one—got selected for the three All-India services .'

Incredible though it may seem, according to the latest available statistics (1965), there were only six Muslim officers in the top two grades of the CSS out of 681. In the next grade, there were only four Muslims out of 2,000. *An* if this is not shocking enough, there were only 21 Muslims out of 9,900 clerks.

Who can blame the Muslims for feeling that some deep-seated prejudice is at work against them?"

And so many other things are here. These should be taken into consideration. After all, the *Illustrated Weekly* s not an organ of the Muslims of India, nor is it an organ of the Muslim League. But even the *Illustrated Weekly* has given some statistics. I do not know how far they are correct. Anyhow it is for the Government to study this matter. The Prime Minister was good enough to make statements in the House and outside the House that special attention will be paid to give employment to the educated Muslims and that they would not be discriminated against. But giving these statements one after another is not going to help the community as a whole. So, I appeal to the hon. Finance Minister and the Government to see that Muslims are taken into confidence and some seats are reserved for them. They should be declared as a socially and educationally backward community, as it is being done today in Tamil Nadu and Kerala. In these two States, Muslims have been declared as a socially and educationally backward community. This is not against the Constitution because the Supreme Court has held that on religion alone, you cannot reserve a seat. For that, a commission was set up in Kerala and that commission went into the matter and found that the Muslim community is backward as far as education is concerned and as far as employment is concerned. So, it is on this basis that reservations have been made. I appeal tt the Finance Minister to make use of his good offices and see that some commission is appointed here also. Let the commission go into these matters and find out whether this community is socially up to the level of the other communities. Let it find out what the position is. If the commission makes a report that this community is socially and educationally a backward community, it is the duty of the Government to lift thfs community to level of the other communities. I hope the Government will pay special attention to this matter.

Another matter to which I would like to draw the attention of the Government is in regard to the Mopla Rebellion of 1921. Sir, freedom fighters and victims of the fieedom movement are being given pensions or other remuneration. But as far as the Mopla Rebellion is concerned, a statement has been made by Mr. Mohsin, the Deputy Home Minister, that the Government does not consider them as freedom fighters. Sir, everybody knows that the Mopla Rebellion of 1921 was a movement started by the Moplas of Malabar at the call of Mahatma Gandhi and Alt Brothers when they called the Khilafat movement; it was nothing but the off-spring of the Khilafat movement. You would find that thousands and thousands of victims are there; their children are there. No pension is being given to them. I appeal to the Government to reconsider their stand and see that the victims of the Mopla Rebellion are also given pensions as freedom fighters.

The other thing is about my own State, Kerala. Everybody knows that Kerala exports coffee, rubber, cashew, etc. and earns foreign exchange for the country as a whole. But at the same time, the financial assistance given to Kerala is quite insufficient for the various development

works. Land reforms have been implemented in letter and spirit. You do not find in Kerala a single landlord. Landlordism has been abolished once and for all. Land has been distributed and permanent ownership is being given to the tenants. But at the same time, financial implications are there in the implementation of land reforms. It is for this that more financial assistance from the Central Government to Kerala is required. With these words, I thank you.

श्री गोलाप बरबोरा (ग्रासाम) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री चव्हाण साहब जब अपना बजट पेश किये थे तो अपने भाषण में उन का कहना था कि इस बजट का मार्केट पर कोई बुरा ग्रसर नहीं पड़ेगा ग्रौर कोई ग्रसर होने से भी बहुत मार्जिनल ग्रसर रहेगा ग्रौर चीजों के दामों को बढ़ने से रोकने का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन बजट को पेश किये हुये ग्रभी कुल दो महीने ही गुजरे हैं ग्रौर बाजार में चीजों का दाम काफी बढ़ गया है, चीजें काफी मंहगी हो गई हैं। जहां तक मुझे मालूम है चव्हाण साहब जिस प्रान्त से ग्राते हैं, वहां ग्राज पांच रुपये किलो गेहूं का दाम है, ग्रौर दस रुपये किलो चावल का दाम है ग्रौर तमाम महाराष्ट्र के लोग जिन चव्हाण साहब को शिवाजी मानते थे ग्राज वहां उन का घेराव हो रहा है। यह समाजवाद का नक्शा है। ग्रभी ग्रभी कमलनाथ जी का भाषण मैं सुन रहा था। बरसों तक मैं उन के साथ रहा। बिहार ग्रौर ग्रासाम का कोना-कोना उन के साथ घूमा हूं। वह कह रहे थे कि गरीबी हटाना कोई एक दिन का काम नहीं है। उसके लिये यू हैव टु टाइटेन दि बेल्ट्स। उस के लिये सेक्रीफाइस करना होगा। जो कुछ ग्राप ने कहा वह ठीक है। प्रधान मंत्री जी ने गरीबी हटाग्रो का नारा लगाया है, लेकिन बाद में विल्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा ग्रौर एक ग्राम सभा में ग्रौर फिर कांग्रेसियों की सभा में भी उन्होंने कहा कि गरीबी हटाना किसी एक प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में संभव नहीं है। यह बात मैं भी मानता हूं किसी भी ग्रंडर डेवलप्ड कंट्री में एक दिन में उस की ग्रार्थिक हालत को सुधारना संभव नहीं है। उसके लिय मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिये काम करना पड़ेगा ग्रौर रिसोर्सेज को टैप करना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस रास्ते में भी हम एक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है कि जिस के कारण एक नया क्लास बन रहा है। बरसों पहले यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के बाद नम्बर दो के एक नेता ने मिलोभान जीलास जिस को बाद में जेल में रखा गया, उन्होंने कहा था कि वहां का जो सोशलिज्म है उसमें एक नया क्लास पैदा हो गया है, जिसके पास सारी सहूलियतें ग्रौर सुविधायें हैं ग्रौर ग्राज हिन्दुस्तान में भी समाजवाद के नाम पर ऐसा ही कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के साथ मैं बम्बई गया था। वहां ग्रोवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिंग हम को देखने को मिली। चूंकि उस की रिपोर्ट मेरे सामने ग्राई इसलिये उस बारे में मैं बोलना चाहता हूं। उस ग्रोवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिंग का ठेका डेढ़ करोड़ रुपये का था। उस ठेके को देने में भी काफी घोटाला रहा वह भी पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट में है, लेकिन उस डेढ़ करोड़ की बिल्डिंग में 35 लाख रुपये का सिर्फ मार्बल लगा। वैसे ही दिल्ली में हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनने वाली है उसमें भी दस लाख रुपये का मार्बल लगेगा। हमारे पार्लियामेंट हाउस के बाथ रूम्स में भी मार्बल लग रहे हैं। तो एक बैकवर्ड कंट्री में क्या जरूरत पड़ती है जगह-जगह मार्बल लगाने की? बम्बई की ग्रोवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिंग में, डेढ़ करोड़ की बिल्डिंग में 35 लाख रुपये का मार्बल लगे जो कि राजस्थान में 11 रुपये क्युबिक फिट मिलता है ग्रौर उसके लिये वह बिल 40, 42 रुपय क्युबिक फिट का दिया गया। तो यह जो तरीका है कि ऊपर के कुछ लोग ग्राराम ग्रौर ग्राशाइस की जिन्दगी बितायें ग्रौर गरीब ग्रौर मध्यम श्रेणी के वर्ग के लिये कहा जाय कि वह देश के लिये त्याग करे, बलिदान करे ग्रौर उन को भूखों मरने का सबक सिखाया जाय यह एक गलत तरीका है। काम करना है तो ग्राइये, हम सब मिल कर करें। हम मानते हैं कि यह एक बैकवर्ड कंट्री है ग्रौर इस को ग्राग बढ़ाने के लिये

[श्री गोलाप बरबोरा]

त्याग करना है, लेकिन इस में बड़े लोग, न्यु रिच क्लास और अफसर लोग और बिजनेसमैन आराम से जिन्दगी बितायें, उन पर एक रात में अशोका और ओबराय होटल में हजारों रुपये खर्च हों और उसी दिल्ली में एक गरीब आदमी जिसके पास अगर जाड़े में कंबल न हो तो वह ठंड खाता फिरे, यह कोई रास्ता एक गरीब देश को आगे बढ़ाने का नहीं है। इसको हमको रोकना चाहिये।

श्रीमन्, रीजनल इम्बैलेंस देश में है और जितना भी हम रीजनल इम्बेलेंस को हटाने के बारे में बोलें हम देख रहे हैं कि आज कुछ इलाके देश में आगे बढ़ते हैं और इलाके भी नहीं बल्कि इलाके के कुछ लोग। इस सदन में हम देखते हैं कि कभी कभी बहस होती है, बंगाल वाले महाराष्ट्र को बोलते हैं कि हमसे इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले गये। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो इश्यू हुये उनकी लिस्ट देखते हैं तो महाराष्ट्र में ढाई सौ और बंगाल में डेढ़ सौ लाइसेंस और हमारा आसाम जैसे प्रान्त में सिर्फ 4 लाइसेंस। तो बहसबाजी होती है फारवर्ड स्टेट के अन्दर लेकिन और भी स्टेट पड़े हुये हैं जहां कि कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलता नहीं है। तो इस तरीके से इस देश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते है। बैकवर्ड जो रीजन्स हैं उनको बराबरी पर लाने के लिये फाइनेंस कमीशन को कुछ ज्यादा एलाटमेंट उन स्टेट्स के लिये करना चाहिये और वहां इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश होनी चाहिये, लेकिन आज आउट-डेटेड एक तरीका है, कहते हैं कि वहां कोई इनफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है और. इसीलिये इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती। तो इनफ्रास्ट्रक्चर कौन बनायेगा इंडस्ट्री लगाने के लिये? इनफ्रास्ट्रक्चर भी आपको तैयार कराना होगा, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसके लिये भी कुछ सहूलियत करें।

श्रीमन, अनएम्प्लायमेंट का सवाल है। देश में इल्लिट्रेसी का सवाल है। अनएम्प्लायमेंट हर पंचवर्षीय योजना में बढ़ता जाता है, पुराने अनएम्प्लाएड जो लोग हैं, उनके साथ-साथ और अनएम्प्लाएड जुड़ जाते हैं। तो बेकारी की समस्या को हल करने के लिये आपका कोई ठोस कदम नहीं है। इस देश में स्कूल, कालेज, युनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हर दस साल में इल्लिट्रेट लोगों की संख्या हिन्दुस्तान में बढ़ती जा रही है, 1961 से 1971 ई० तक की सैंसस रिपोर्ट जो है उसके अनुसार निरक्षर लोगों की, इल्लिट्रेट लोगों की, टोटल संख्या करीब 7 करोड़ बढ़ी है।

उसी तरह भूमि सुधार की बात आप करते हैं, भूमिहीनों को जमीन देने की बात करते हैं, लेकिन 1961 से 1971 ई० तक से सैंसस के अनुसार दस साल में भूमिहीनों की तादाद, पापुलेशन 16 परसेंट से 22 परसेंट तक बढ़ गई है। इस ढंग से आप एनालाइज कर के देखिये तो देश में गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ज्यादा किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं, ज्यादा लोग अनपढ़ होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ समाज का सब कुछ साधन, पूंजी, जा कर के कुछ लोगों के हाथ में जमा हुई है और वह भी ब्लैक मनी के रूप में और उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं फिजूलखर्ची में देश के रिसोंसेज को बढ़ाने में उनको कोई मदद नहीं मिलती है।

श्रीमन्, जहां रीजनल इम्बैलेंस की बात हम कहते हैं तो उसी के साथ जुड़ी हुई है एक और समस्या और वह समस्या है ईस्टर्न रीजन की जो जूट और टी इंडस्ट्री है उसकी। आसाम जैसे प्रान्त में 11 लाख बेल्स जूट पैदा होता है और वहां सिर्फ एक जूट मिल है जिसमें 1 लाख बेल्स की खपत है, वहां कम से कम तीन और जूट मिल हो सकती हैं। वैसे ही चाय का जो उद्योग है हिन्दुस्तान में उसकी 50 फीसदी चाय आसाम में पैदा होती है, लेकिन वहां चाय इंडस्ट्री की हालत भी बहुत खराब है। अभी-अभी एस्टीमेट्स कमेटी की 28वीं रिपोर्ट में टी इंडस्ट्री के बारे में कुछ सजेशंस दिये गये हैं। टी इंडस्ट्री का काफी दिनों से डिमांड रही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटायें और एक्सपोर्ट ड्यूटी फर्स्ट मार्च, 1970 ई० से हटाई और रिबेट दिया गया एक्सपोर्ट पर 15 अप्रैल, 1970 ई० से। लेकिन जहां 50 पैसे की एक्सपोर्ट ड्यूटी

थी वहां एक्साइज ड्यूटी का एक नया ऐक्ट लागू किया गया—20 पैसे से लेकर एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां है करीब 1 रु० 50 पैसे तक। 5 ज़ोन्स बनाये है जिसमें कई एक जोन्स में 1 रु० 50 पैसे तक एक्साइस ड्यूटी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ करके जो कुछ भी राहत टी इन्डस्ट्री को दी गई उससे ज्यादा टैक्स उनसे वसूल किया गया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा कर। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। इसकी सारे हिन्दुस्तान की इन्डस्ट्री की हालत बहुत खराब है, दुनिया की मार्केट में भी जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है—एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में है—सीलोन 212.2 मिलियन किलो० में से 208.3 मिलियन किलोग्राम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और हिन्दुस्तान का 1970 का फिगर भी है कि वह 421.28 मिलियन किलोग्राम्स चाय पैदा करके 208.4 मिलियन किलोग्राम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इस सबके बारे में सरकार का कहना है कि टी बोर्ड है और एक सब-कमेटी है उसके जरिये देखभाल कर रही है। लेकिन जहां तक सवाल है चाय उद्योग को बचाने के लिये कुछ हो नहीं रहा है। चाय उद्योग की जनरल प्राफिटेबिलिटी का भी सवाल है। इसकी प्राफिटेबिलिटी, 1965–66 में जहां 4.3 परसेन्ट रही वह बढ़ कर 1967–68 में 6.5 परसेन्ट हुई लेकिन 1968–69 में फिर 2.1 परसेन्ट में आ गई। और साथ ही साथ मजदूरों का भी सवाल है चाय उद्योग में। मैं असम से आता हूं, उस प्रान्त में 4 लाख लोग चाय बागान के मजदूर आज बेकार हैं। वैसे ही हिन्दुस्तान के और उद्योगों में लाखों लोग बेकार हो रहे हैं।

अभी-अभी पे कमीशन की रिपोर्ट जो कुछ भी अखबारों में आई है वह पढ़ कर मजदूर खुश नही है। साथ ही साथ, पे कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के बारे में सरकार का क्या रुख है, वह भी अभी तक कहा नहीं जा रहा है। इसके अलावा, पे कमीशन की रिपोर्ट, जहां तक लोकल बाडीज का सवाल है, पंचायत और म्युनिसिपल इम्प्लायीज वगैरह का सवाल है, उन लोगों में लागू होगी या नहीं। स्टेट एम्प्लायीज के हित में सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट का क्या सम्बन्ध रहेगा, इसके बारे में भी कहा नहीं गया साथ ही साथ, रेलवेमैन तथा और भी कर्मचा बोनस और मिनिमम वेजेज के सवाल को लेकर अगले एक महीने में हड़ताल में जाने की धमकी दे रहे हैं। इसके ऊपर भी सोच विचार होना चाहिये। इस सब परिस्थिति को देखते हुये मैं यह मानता हूं कि देश की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, इस पर सरकार का कोई काबू नहीं है और इसलिये आज हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर महोदया कोई भी सवाल का इस सदन में, यहां रहते हुये भी, जवाब नहीं दे कर पब्लिक मीटिंग्स में—कहीं कानपुर में, कहीं कोचीन में, कहीं बंगलौर में—बोलती हैं और खास कर अपोजिशन पार्टी पर हमला करती हैं। कांग्रेस के लोगों का यह भी कहना है कि गांव का किसान कहीं मण्डियों में गेहूं ला कर नहीं दे रहा है तो वह इसलिये कि ये अपोजिशन के लोग जाकर गलत प्रचार किये है, लोगों में एक डर पैदा किया है। अपोजिशन तो हिन्दुस्तान में ऐसा खास है नहीं। जो कुछ भी है, इस अपोजिशन को आज जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज हरियाणा और पंजाब की मण्डियों में लोग अनाज लाने के लिये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे अनाज लेंगे 76 रु० क्विंटल और आज बाजार में 1 रु० 50 पैसे या 1 रु० 60 पैसे किलो के नीचे आटा नहीं मिल रहा है। यह हालत है। उधर बिजली का दाम बढ़ा, खाद के दाम, पानी के रेट्स ज्यादा हो गये। इतना सब कुछ होते हुये, जो किसान हैं, उनसे अनाज जो आप लेंगे उसके वाजिब दाम क्यों नहीं देते हैं। दाम तो आपके तय किये हैं लेकिन किसान के घर में जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उनको किफायती दाम पर देने के लिये क्या व्यवस्था आपने की है? कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिये किसान घबड़ा रहे हैं और इस बात को लेकर सारे हिन्दुस्तान में—आपको चेतावनी दे रहा हूं एक साधारण नागरिक की हैसियत से—एक बहुत बड़ा व्यापक असंतोष फैल रहा है जो कि और भी ज्यादा फैलने वाला है। और इस चीज को और वहां की जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये महाराष्ट्र और गुजरात में जो कार्यवाही की गई

[श्री गोलाप बरबोरा]

गोली और लाठी का जो इस्तेमाल किया गया, वह बहुत ही शर्मनाक है। आपको देश की परिस्थिति को सुधारना होगा और इस तरह की हालत को गोली और लाठी से सुधारा नहीं जा सकता है। आपको देश में बढ़ते हुये दामों को रोकना होगा और अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो श्री चव्हाण साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये।

कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापर्डे (महाराष्ट्र): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट का मैं मन पूर्वक स्वागत करती हूं। इस बजट को पेश करते वक्त लोगों को कई अपेक्षा थीं, लेकिन उस अपेक्षा के मुताबिक बजट पेश नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। वह ठीक भी है। एक बात आपने अवश्य की और वह यह है कि आपने गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया। आपने गरीबों पर भले ही टैक्स न लगाया हो, लेकिन गरीबों को इस बजट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। इतना तो मैं अवश्य कहूंगी कि अगर उन्हें राहत मिली होती, तो शायद आज हम बढ़ती हुई कीमतों को न देखते और इस बढ़ती हुई कीमतों में आज उन लोगों की चीजों को खरीदने की समर्थता नहीं रह गई है।

दूसरी बात मैं महाराष्ट्र के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि नागपुर, शोलापुर, मालेगांव तथा अन्य जगहों पर जो परिस्थिति का निर्माण वहां पर पिछले कुछ दिनों में हुआ वह बहुत ही खेदजनक है। पहला कारण तो इस परिस्थिति के निर्माण होने का खाद्यान्न रहा, लेकिन साथ ही साथ एक और भी कारण था जिस कारणवश वहां पर परिस्थिति खराब हुई और वह था काटन यार्न की कमी और इन दो कारणों की वजह से उन इलाकों में परिस्थिति खराब हो गई और जटिल बन गई। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहती हूं कि पिछले 15 दिनों से नागपुर तथा उसके इर्द-गिर्द गांवों में सूत, अनाज और अन्य दुकानों की भयंकर लूटमार हुई। महाराष्ट्र के अन्य भागों में भी विशेषत: नागपुर, मालेगांव, शोलापुर, नासिक, ओडार आदि गांवों में उसी प्रकार से अनाज आदि दुकानों की लूटमार की गई। यहां तक कि सिन्नर में कचहरी तक को जलाया गया है। पुलिस ने इस उत्पाद को रोकने के लिये लाठी और गोली का सहारा लिया जिससे कई लोग जख्मी हुये और कई लोगों की जानें गई। सामान्यत:, कानूनन नहीं तोड़ने वाला महाराष्ट्र का जनसमुदाय इस तरह से कानून तोड़ने पर विवश हुआ। इसका मूल कारण तथा सूत के व्यापार का सरकारीकरण होने के बाद आवश्यक कदम सरकार को उठाने चाहियें थे और अनाज तथा सूत का वितरण योग्य मात्रा में तथा योग्य मशीनरी द्वारा वितरण करना चाहिये था, जो सरकार नहीं कर पाई। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश से 25 से 30 लाख हैंडलूम्स हैं और करीब दो अढ़ाई लाख लोगों की जीविका इस चीज पर निर्भर करती है। केवल महाराष्ट्र में एक लाख 85 हजार हैंडलूम्स हैं और 90 लाख लोगों की जीविका इस चीज पर निर्भर करती है। इसमें से 85 हजार तो कोआपरेटिव सैक्टर में हैं और बाकी सारे कोआपरेटिव सैक्टर के बाहर हैं। आज तक कोआपरेटिव क्षेत्र के बाहर के हैन्डलूम्स के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार बिलकुल जिम्मेदार नहीं थीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के तिड़के-समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद 2 अक्तूबर, 1971 से महाराष्ट्र में हैन्डलूम, पावरलूम तथा सहकारी वस्त्र निर्माण संचालनालय का निर्माण हुआ और महाराष्ट्र राज्य में हैन्डलूम कारपोरेशन का 1 अक्तूबर 1971 को निर्माण हुआ। इस संस्था का उद्देश्य था सहकारी क्षेत्र के बाहर वाले हैन्डलूम को संरक्षण देना तथा उनके माल की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार करना। लेकिन दुर्भाग्य से तिड़के समिति की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया, जिसके कारण बुनकरों की समस्या दिन-ब-दिन जटिल होती गई, उदाहरण के लिये डाय हाउस, सायसिंग प्लान्ट, सरकारी कर्मचारियों को हैन्डलूम का कपड़ा खरीदने के लिये एक महीने का एडवान्स देकर खादी के सिवाय सरकारी तथा गैर-सरकारी दफ्तरों में

हैन्डलूम का कपड़ा इस्तेमाल करना आदि अनेक योजनाओं पर डेढ़ वर्ष के बाद भी अमल नहीं हो सका। राज्य सरकार के बजट में जो पैसा बुनकरों की योजनाओं के लिये था, उसे उपयोग में नहीं लाने के कारण वह पैसा सरकार को लौटा दिया गया। राज्य शासन के बुनकरों को दिये हुये आश्वासन की पूर्ति न करने के कारण और तिड़के समिति की सिफारिशों को अमल में न लाने के कारण बुनकरों की समस्या काफी बिगड़ गई।

बुनकरों को सूत अधिक भाव से खरीदना पड़ता है कलर कैमिकल्स के भाव में तेजी होने के कारण बुनकरों के माल की बिक्री की कीमत नहीं बढ़ सकी। उनको हैन्डलूम का धंधा चलाना मुश्किल हो रहा है। सूत के बारे में आर्टीफीशियल शार्टेज निर्माण की जा रही है, यह सत्य है। व्यापारियों ने यह परिस्थिति जानबूझ कर निर्माण की हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसका कारण यह भी है कि बिजली की कटौती 16 प्रतिशत है। सरकार ने यह बिजली कटौती का रुख सूत गिरणी तथा मिल के सूत विभाग के बारे में नहीं अपनाया होता तो बुनकरों के लिए शायद यह समस्या गम्भीर न बनती।

इस वर्ष महाराष्ट्र में तीन लाख (गाठें) बेल्स काटन पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने सूत के वितरण की व्यवस्था ठीक से नहीं की, वरना शायद ही यह परिस्थिति निर्माण होती। इस मार्च महीने तक बुनकरों के पास सूत नहीं पहुंच सका। सूत के भाव में काफी तेजी आ गई है और इस परिस्थिति का लाभ व्यापारियों ने उठाया है। नतीजा यह निकला कि भारी दाम में सूत खरीदना गरीब बुनकरों के बस की बात नहीं थी और उनके सारे रास्ते बन्द हो गए। सूत नहीं, इसलिए काम नहीं, काम नहीं इसलिए बढ़ती हुई मंहगाई मे खाने के लिए अनाज नहीं। इसी कारण बुनकर जनता तंग आकर चिढ़ गई और उन्होंने लूटमार की परिस्थिति नागपुर तथा अन्य जगह निर्माण की।

महाराष्ट्र में 1 लाख 85 हजार हेन्डलूम्स में से 1 लाख विदर्भ में हैं। इसमें से नागपुर शहर में 27 हजार हैं। उस पर डेढ़ लाख लोगों की उपजीविका निर्भर है। सूत की परिस्थिति सुधारने के लिए मैं अपनी दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहती हूं:–

1. राज्य सरकार सूत गिरणी तथा मिलों के सूत विभाग पर लगाया हुआ बिजली कटौती का बंधन शिथिल करें।

2. मिल और सूत गिरणी चौबीस घंटे उत्पादन करके हैन्डलूम के लिए लगने वाले हैंक बेल्स के रूप में ऊंचे नम्बर का सूत उत्पादन करें।

3. राज्य सरकार को सुयोग्य यंत्रणा निर्माण करके बुनकरों को प्रत्यक्ष रूप में सूत का वितरण करना चाहिए और उसके अमल पर सख्त नजर रखनी चाहिए।

वास्तव में महाराष्ट्र सरकार को अनाज के व्यापार के सरकारीकरण के बाद अनाज की वसूली जिस तेजी से करना आवश्यक था उस तेजी से वसूली नहीं कर पाई। आज भी इतना सारा होने के बाद भी राज्य में किसानों से अनाज की वसूली संतोषजनक नहीं है। अनाज और सूत के व्यापार को सरकार ने जो अपने हाथ में लिया है उसको किसी तरह से असफल करने की व्यापारियों ने ठान ली है। इस सारी स्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि जनता उत्तेजित होकर दंगे-फसाद करने पर मजबूर हो गई है। इतना ही नहीं विरोधी लोग सीधी-सादी जनता को बहका कर दंगा-फिसाद कराने में और हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे रहते हैं।

इतना ही नहीं, मैं तो आपको इसके आगे भी जाकर कहना चाहती थी और वह है कि जैसे पिछली एक मई को सारा नागपुर ही नहीं सारा विदर्भ बन्द का काम दिया गया था उस वक्त हम सब लोगों के मन में एक प्रकार का भाव था कि यह सही माने में सेपरेट विदर्भ की मांग कर रहे है। लेकिन हमने यह देखा है कि सारे लोग इतनी तादाद में अपनी-अपनी दुकानें बन्द करके भयभीत हो गये थे। उसका कारण यह था कि दुकानदारों ने सैपरेट विदर्भ की डिमांड

[कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापर्डे]

पर अपनी दुकानें बन्द नहीं रखे हुए थे, बल्कि उसका कारण यह था कि बुनकरों की जटिल समस्या काटन यार्न की थी। दूसरी बात बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान थे, तीसरी बात यह रही कि अनाज की समस्या किसी स्टेट में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां न हो। जहां सूखा पड़ा है वहां निश्चित तौर पर फूड प्राब्लम है। इन्हीं तीन कारणों से विदर्भ बन्द रहा। दूसरा, मुझे यह लगता है कि नागपुर महाराष्ट्र का सेकिंड कैपिटल है सेकिंड कैपिटल होने के बावजूद भी आज विदर्भ के लिए जो कहते हैं कि हम सैपरेट विदर्भ चाहते हैं, उसका कारण मुझे लगता है कि जैसे बम्बई शहर में बड़े-बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, उसे कंपेरिजन की दृष्टि से देखते हैं तो विदर्भ में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग से अलग विदर्भ की यह मांग, यह चीज निकाल दें, अगर हमारी सरकार विदर्भ में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाये और विदर्भ का उत्थान कर सके तो लोगों के दिमाग से यह बात निकल जाएगी।

अन्त में मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में काटन यार्न और फूड सिचुएशन का निर्माण हुआ है। इसकी ओर अधिक ध्यान देकर महाराष्ट्र की जनता को दंगे फसादों से बचाने की चेष्टा करें।

मुझे आपने अपने विचार सदन के सामने रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA] (Mysore) : Mr. Vice-Chairman, Sir, as usual we are getting time at the tail end of the day and instead of speaking here I can as well go over to the Finance Minister and present my case to him because there is nobody here.. .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Mr. Gowda, if you do not want to speak now...

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: No, no; I do want. I am only saying this is the situation which I always find myself in every time I rise to speak.

SHRI OM MEHTA : I would request him to join some party and to find himself in a better situation.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Thank you very much; I will certainly consider that.

Mr. Vice-Chairman, this Rajya Sabha participating in the discussion on the Finance Bill is more or less a formality. We will have made our suggestions during the general discussion on the Budget and now that Mr. Chavan has already sot the Finance Bill nassed in the Lok Sabha it is only a mere formality and whatever views we may have to express we would express so that at least for the next Finance Bill he could give some consideration to the points which we make now.

In his speech when he introduced the Bill, the avowed object was to promote savings and investment, to enlarge employment opportunities, to ensure minimum basic amenities to all citizens and to give a boost to our exports. With the limited resources available and in the difficult situation in the country I should say that Mr. Chavan has tried to do his best but unfortunately when we find the final outcome of this Bill I do not know to what extent these objectives could be achieved by the Finance Bill which is now being passed.

The first thing I would like to mention here is about a subject in which I myself am concerned and Mr. Chavan was good enough to start off his speech today with that, that is, the aggregation of the agricultural income-tax and general income-tax for the purpose of computing the tax. When the general discussion on the Budget took place, I myself made this very point and requested him to give us some concession or consider giving a rebate for the agricultural income-tax which is paid, in

at least the States in which the agricultural income-tax Act is in force. I am very happy that he has considered and conceded that point and I congratulate him on that and I thank him for that. While doing that I would like to mention here certain difficulties which arise. The agricultural income-tax Act is in existence in the three Southern States, *i.e.,* Mysore, Madras and Kerala, where more than general agriculture, commercial crops like plantation crops give the major yield from agricultural income-tax. I understand that there are agricultural income-tax Acts in Assam, Maharashtra and other places where it covers general agriculture. In Maharashtra the exemption limit is very high, *viz.,* Rs. 36,000 and so the actual incidence of Vix Is very low. In the Southern States the agricultural income-tax Acts are exactly on the lines of the Central Income-tax Act, which taxes income over Rs. 5,000. Why I am mentioning this here is that the agricultural income-tax which is paid will be given a rebate as provided in clause 8 while calculating the aggregate income now, but there are still certain other difficulties which will arise, like losses which will accrue out of agricultural income, the suggestion has been made that it will be set off only against the agricultural portion of the income. When there is a higher earning by aggregating the two, the tax will be at the higher rate on the non-agriculture portion, but when there is a loss, it is set off only against the agricultural portion of it This will not give the relief which I thought it would provide. Then, another practical difficulty about this is that the Central income-tax assessing authorities will have to wait until the agricultural income-tax assessments are finalised for determining in such States the agricultural income portion of it. I suggest that this matter must be taken up with the State Governments to see that the agricultural income-tax assessments are completed by the time the Central assessments commence. Otherwise, there will be delay and there will be difficulties for the assessees.

Another thing I would like to mention Is that in certain States even where agricultural income-tax is in force, agricultural commodities like paddy, wheat and rice are not covered. How are they going to be assessed? Another problem is when you come to States like Haryana whe're there is no agricultural income-tax. If there are people with non-agricultural income and also agricultural income, how do you propose to assess the agricultural income? Since there is no Act, some method has to be found. I cannot say whether any method has been introduced for that and whether it is going to be done ar the stage of the rules. Unless that is «ione, the entire assessment on the non-agricultural income of persons who have also agricultural income in those States will be held up for a long time. Some method will have to be found for that. No doubt, the relief he has provided is considerable, but I would like to point out here the case of an assessee who has a small non-agricultural income and a large agricultural income. For example, let us take an agriculturist who has husbanded his resources and he has put his money in the banks or in shares or in other investments and mainly out of that he gets about Rs. 20,000 ay non-agricultural income. This sum of Rs. 20,000 now attracts a tax of, say, 20 or 23 or 25 per cent at the most. Then, let us say his agricultural income is Rs. 60,000 or Rs. 80,000. When this aggregation comes, the aggregate income will be Rs. 1,00,000 and this sum of Rs. 20,000 will be taxable at the rate applicable to Rs. 1,00,000 minus the agricultural income-tax he has paid, if any. That will immediately put up the rate of tax for the non-agricultural income to 70 or 75 per cent. So, the investment climate that he has provided for the small investor by giving rebate upto Rs. 3000 rebate of income-tax for investment in the bank deposits etc., will be nullified by this taxation going up to 70 to 80 per cent. Out of the Rs. 20,000 he will hardly get Rs. 5,000 and how does the Government expect people to make investments in the nationalised banks or put in shares, etc? This is a hardship which is still there. We can know it only at the working stage. Otherwise, if you take only the case of a person

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

who has only Rs. 15,000 of agricultural income, it does not give this picture at all. This is a point which I would like him to bear in mind and see what relief he can provide by the time this comes into force in 1974.

Going into the details of the Finance Bill about the resources which have been tried to be mobilised, direct and indirect resources, the non-tax resources proposed to be raised are very limited. As for example, I would like to quote here that a commendable effort is being made to make the public sector industries yield a better return, which will form as non-tax resources, and he has enumerated certain measures which have been taken and also the efforts which are being made by the Government. But I am sorry to say that in spite of that, we see that out of the five thousand crores of investment in public sector, even if we get 5 per cent return on that, we should have Rs. 250 crores. But as against this the public sector shows an approximate cumulative loss of Rs. 18 crores now. A very considerable effort has to be made in this direction now and in future; otherwise, this will upset any of the non-tax resources which you would like to generate for the economy.

Then when we come to the question of direct taxes which are not very considerable but look at the taxation structure, India is probably one of the highest individually taxed countries in the world. Even the Wanchoo Committee in its recommendation has felt that unless something is done about marginal taxation at the highest level— which goes up to 97 per cent—there is hardly any saving and any incentive for saving and the savings will be only from the tax-evaders or the smugglers. That is the only saving section. This is a matter which should be looked into. But, unfortunately, when the other recommendations of the Committee are being considered, this has been left out. I hope that some consideration will be given to It so that the tax will be in such a way that sufficient incentive will be available for individual saving.

I would like to point out another thing that is in view of the eroding value of the rupee, this exemption limit which has been put at Rs. 5000 is rather ridiculously low by today's comparison. It should have been raised to Rs. 7500 at least. Hardly the rupee is worth about thirty paise only, and I hope that in the next Budget he j v/ould consider raising the exemption limit to Rs. 7500 which will give relief to the salaried people and also the smaller income group and it will also save the expenditure in covering this vast number of assessees whose exemption limit is just Rs. 5000.

With regard to the savings, with the ever-increasing price-line with respect to consumer goods and also essential commodities, where is the scope for saving? Money circulation in comparison to the rate of growth has increased too high. Actually, it is an accepted fact that money supply should not be more than two to three per cent of the rate of growth. If we look at the picture we find that when the rate of growth has been hardly 1.5 per cent, the money supply has increased from two to three per cent. How does it allow for any citizen to make any saving? So, this becomes only a matter put on paper but in actual practice you could not have any saving, and the savings will be only of the tax-evaders and others. Another thing is, Mr. Chavan...

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) : You have made your points.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: Sir, give me a few minutes. It is the tail end and you can give me another five or ten minutes. Or I am prepared to continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You take five minutes more and conclude.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Sir, I am speaking only on the Finance

Bill. I have not gone to the entire gamut of the political situation in the country...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You have made your major points.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: . .and you cut me out within ten minutes.

SHRI S. S. MARISWAMY: He can continue tomorrow.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Yes, I will take ten minutes tomorrow and finish. That is better.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You can take five minutes now and complete.

SHRI S. S. MARISWAMY: Let him continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): All right. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 8th May, 1973.

MGIPRRND—16RSS/73—S3c. II (Night)—18-7-73—570.